●वर्ष-5
●अंक-273
रायपुर, गुरुवार
02 जुलाई 2026
●पृष्ठ-8
●मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज–8>> शिक्षा से ही बनेगा उज्ज्वल...

30 दिन जेल में रहने पर जाएगी कुर्सी

सिफारिशों के साथ जेपीसी की रिपोर्ट तैयार; मानसून सत्र में हो सकता है पारित

नई दिल्ली। संविधान के 13वें संशोधन विधेयक का प्रस्ताव संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के पास है। इसमें मंत्रियों को हिरासत में लिए जाने पर, 30 दिन बाद उन्हें पद से हटाने का प्रावधान भी है। 17 जुलाई को जेपीसी की कमेटी इस प्रस्ताव पर रिपोर्ट पारित कर सकती है। सूत्र बताते हैं कि जेपीसी की रिपोर्ट में, सबसे विवादित प्रावधान को बरकरार रखे जाने की संभावना है।

जेपीसी के पास भेजे गए इस प्रस्ताव के विवादित खंड में यह प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किए जाता है या हिरासत में लिया जाता है, तो दिन तक हिरासत में रहने के चलते उन्हें स्वत: पद से हटा दिया जाएगा। जेपीसी राजनीतिक प्रतिशोध के लिए कानून के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ सतर्क सुझाव भी शामिल कर सकती है।

पारित कराने की तैयारी में सरकार

सूत्रों के अनुसार, संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सरकार की योजना इसी सत्र में ही विधेयक पर चर्चा के साथ ही इसे पारित कराने की भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल अगस्त में यह विधेयक पेश किया था

और इसकी जांच के लिए अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय जेपीसी का गठन किया गया था।

विपक्षी दलों ने किया था जेपीसी का बहिष्कार

कांग्रेस समेत विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के अधिकांश सदस्यों ने जेपीसी का बहिष्कार किया था। उनका तर्क था कि समिति में भाग लेना व्यर्थ है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी विपक्ष की चिंताओं को आसानी से नजरअंदाज कर देगी। हालांकि, सत्तारूढ़ एनडीए के सदस्यों ने विपक्ष के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि प्रस्तावित कानून में प्रावधान अलोकतांत्रिक, संघीय विरोधी और प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांत के विपरीत हैं।

ऐसा अनुमान है कि सत्ता पक्ष की तरफ से यह तर्क दिया है कि कम से कम तीन बार जमानत मांगने के लिए 30 दिन पर्याप्त हैं, इसलिए यह प्रस्ताव प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है।

दुरुपयोग के लिए सिफारिशों पर सभी सहमत

हालांकि, सूत्रों के अनुसार सत्ताधारी गठबंधन के सांसदों, विपक्ष और यहां तक कि तटस्थ सदस्यों को भी यह विश्वास था कि विधेयक के मसौदे में कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान जोड़े जाने चाहिए। उन्होंने बताया कि यह सुझाव सिफारिशों का हिस्सा होगा। समिति द्वारा यह सिफारिश किए जाने की भी संभावना है कि कानून के दायरे को व्यापक बनाए रखने के बजाय, प्रस्तावित कानून के प्रावधानों का उपयोग करने के लिए अपराध की प्रकृति पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं। सूत्रों बताते हैं कि जेपीसी में विपक्षी सांसद रिपोर्ट पर असहमति जता सकते हैं। हालांकि, इस समिति में बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों का दबदबा है। हालांकि, इसमें एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले भी सदस्य हैं। इसके अलावा वायएसआरसीपी के निरंजन रेड्डी सिरगापुर (राज्यसभा सांसद) भी 31 सदस्यीय समिति का हिस्सा हैं।

संविधान के 130वें संशोधन विधेयक, 2025 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी मंत्री पर पांच वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा वाले अपराध का आरोप है और उसे लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार करके हिरासत में रखा गया है, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा या फिर हिरासत के 31वें दिन स्वत: ही उसे पद से हटाया जा सकता है।

मोदी 3.0 कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा गर्म

नई दिल्ली>।केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार इस समय नीट पेपरलीक, सीबीएसी कॉपी पुनर्मूल्यांकन, श्री राम जन्मभूमि मन्दिर दान में गबन, सीएम मोहन यादव पर लगे आरोपों से घिरी हुई है। विपक्ष द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को हटाने की माँग के बीच मीडिया में यह चर्चा गर्म हो चुकी है कि मोदी कैबिनेट में शीघ्र ही बड़ा फेरबदल होने वाला है।

दो केंद्रीय मंत्रियों (रवनीत सिंह बिट्टू और जार्ज कुरियन) को दुबारा राज्य सभा न भेजे जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में दो जगह खाली हुई हैं। पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाए जाने उनकी भी कैबिनेट से विदाई तय है। साफ है कि मोदी कैबिनेट में वैकेंसी है। अब यह पीएम मोदी और भाजपा आलाकमान पर निर्भर है कि वह इन वैकेंसी को कब भरते हैं। कई राजनीतिक जानकार दावा कर रहे हैं कि मोदी कैबिनेट के कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कुछ का मंत्रालय बदल सकता है।

साल 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने। यह उनका तीसरा कार्यकाल है। अपने पहले दो कार्यकाल में पीएम मोदी ने कुल चार बार कैबिनेट में फेरबदल की थी। आइए एक नजर डालते हैं, मोदी कैबिनेट के पिछले परिवर्तन पर ताकि हम समझ सके कि पीएम मोदी अपनी कैबिनेट में किस तरह के बदलाव करते रहे हैं।

सबसे पहली बार 10 नवंबर 2014 को मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। पीएम मोदी ने 6 महीने पहले ही 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब पीएम मोदी ने 45 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी और जब विभागों का बंटवारा हुआ तो कई मंत्रियों को एक से अधिक विभाग दिए गए थे। मंत्रियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा था, ऐसे में 10 नवंबर 2014 को मोदी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। नवंबर 2014 में कुल 21 मंत्रियों को शामिल किया गया था। इसमें चार कैबिनेट, 14 राज्य मंत्री और तीन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल थे।पहले मंत्रिमंडल विस्तार में जेपी नड्डा को पहली बार सीधा कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। तो वहीं शिवसेना से आए सुरेश प्रभु को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सुरेश प्रभु को बाद में रेल मंत्रालय मिला था। इसी दौरान शिवसेना और बीजेपी के रिश्ते में पहली बार खटास सामने आई थी। शिवसेना के अनिल देसाई को शपथ नहीं दिलाई जा सकी क्योंकि वह वहां पर मौजूद नहीं थे।राजीव प्रताप रूडी-बंडारू दत्तात्रेय को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था। साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी के रूप में मुस्लिम चेहरे को भी जगह मिली थी। राज्यवर्धन राठौर और रामकृपाल यादव को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। बाबुल सुप्रियो को भी पहले मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान मोदी कैबिनेट में जगह मिली थी।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित सलियाटोली में 4.37 करोड़ रुपये की लागत से 250 सीटर सर्वसुविधायुक्त नालंदा परिसर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यह परिसर क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक, तकनीक आधारित और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन का वातावरण उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने 21 जून 2025 को इस परियोजना का भूमिपूजन किया था।

शुभेन्दु अधिकारी ने घुसपैठियों का दाना पानी बंद किया

नईदिल्ली। घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। देश में अवैध घुसपैठ और बदलती जनसंख्या संरचना पर केंद्र सरकार पूरी तरह आक्रामक मोड़ में आ चुकी है। जनसांख्यिकीय बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को अपनी पूरी रणनीति बता दी है, जबकि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने घुसपैठियों का दाना पानी बंद करने की दिशा में सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। लाखों संदिग्ध लाभार्थियों के नाम सरकारी योजनाओं से हटाए जा चुके हैं और नागरिकता की कड़ी जांच शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार अब साफ संकेत दे चुकी है कि अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान और जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने की हर कोशिश पर निर्णायक प्रहार होगा।

हम आपको बता दें कि जनसांख्यिकीय बदलावों पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत की। समिति ने साफ कर दिया है कि वह देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर जमीनी सच्चाई का प्रत्यक्ष अध्ययन करेगी, ताकि अवैध घुसपैठ, संदिग्ध नागरिकता और जनसंख्या असंतुलन जैसे गंभीर मुद्दों पर ठोस निष्कर्ष निकाले जा सकें।समिति ने केंद्रीय गृहमंत्री को बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पहले ही विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए प्रश्नावली तैयार कर ली गई है। इसके जरिये स्थानीय प्रशासन, सरकारी विभागों और केंद्रीय मंत्रालयों से विस्तृत तथ्य जुटाए जाएंगे। गृहमंत्री ने समिति की रणनीति की सराहना करते हुए गृह सचिव को निर्देश दिया है कि समिति को हर स्तर पर पूरा सहयोग उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्होंने समिति से जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें देने को कहा है। यह पूरा अभियान उस हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन का हिस्सा है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को की थी।

मोदी सरकार का मानना है कि अवैध घुसपैठ केवल सीमा सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है।

प्रमुख समाचार

अखिलेश यादव के जन्मदिन पर मंत्री राजभर ने कसा तंज

लखनऊ। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। इस मौके पर उन्होंने अखिलेश यादव को आरामतलबी और आलस्य त्यागने की सलाह दी है। उन्होंने एक्स पर जारी

बयान में कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। बहुत सोचा कि आपको उपहार में क्या दूं...आप ठहरे बड़े घर के बेटे, पिताजी पूर्व सीएम और रक्षामंत्री रहे, आप खुद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आलिशान बंगलों में जीवन गुजरा है। हम भला क्या दे सकते हैं आपको। मगर उम्र और अनुभव में बड़ा होने के नाते एक सलाह हम आपको दे सकते हैं। सलाह यही है कि आप अपनी आलसी और आरामतलबी वाली जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए, एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी हो सके त्याग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।

ढाई साल में राम मंदिर क्यों नहीं गए अमित शाह : केजरीवाल

नई दिल्ली। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावे की बड़े पैमाने पर हुई चोरी को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें उन्होंने उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर बनने के बाद पिछले ढाई साल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

एक बार भी राम मंदिर में भगवान श्री राम के चरणों में माथा टेकने नहीं गए। केजरीवा ने दावा किया कि आज के समय में आम आदमी पार्टी ही देश की असली सनातनी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, राम मंदिर बनने के बाद से गृह मंत्री अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर में भगवान श्री राम के चरणों में माथा टेकने नहीं गए। इन ढाई वर्षों में अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए। कुछ दिन पहले मुझे कुछ लोगों ने यह बात बताई। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि जो लोग भगवान राम के नाम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वे मंदिर बनने के बाद से भगवान राम का आशीर्वाद लेने राम मंदिर नहीं गए? मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है?

उद्धव गुट में भगदड़ के बाद घर में घमासान

मुंबई। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना में वफादारों के बीच असंतोष के संकेत तब मिले, जब पार्टी सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी में कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा दिया गया। उनके ये बयान यूबीटी सेना छोड़ने और

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली विरोधी सेना में शामिल होने वाले छह सांसदों के कुछ दिनों बाद आए हैं। राउत ने कहा कि हमें व्यक्ति के चरित्र को पहचानने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिल जाता है और इससे पार्टी के वफ़ादार लोगों को दुख पहुँचता है। उन्होंने पार्टी के भीतर आत्म-मंथन करने की बात कही। उनकी ये बातें मंगलवार को यूबीटी सेना के सुनील शिंदे की कही बातों से मिलती-जुलती थीं, जब पूर्व विधायक सचिन अहीर शिंदे के नेतृत्व वाली सेना में शामिल हुए थे। सुनील शिंदे ने भी पार्टी के भीतर आत्म-मंथन की मांग की है, हालांकि उन्हें अहिर के पार्टी छोड़ने के बावजूद वर्ली सीट पर यूबीटी सेना की जीत की उम्मीद है।

सामना में शिवसेना-यूबीटी ने भाजपा पर साधा निशाना

मुंबई। शिवसेना ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उसकी देशभक्ति और हिंदुत्व केवल एक दिखावा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा का आचरण रावण के वंशजों जैसा है। पार्टी ने कहा, भले ही भाजपा रावण को बुरा मानती हो, लेकिन हिंदू

समाज को यह याद रखना चाहिए कि रावण पाखंडी नहीं था। उसने भाजपा की तरह राम मंदिरों के दान-पात्रों से चोरी नहीं की थी। सामना के संपादकीय में कहा गया कि यदि भगवान राम के नाम पर हो रही कथित लूट, देश की जमीन पर कब्जा, लोकतंत्र और संविधान को कमजोर किए जाने जैसी घटनाओं पर किसी को दुख या शर्म महसूस नहीं होती और लोग इसे ही राजनीति मान बैठे हैं, तो विष्णु का 13वां अवतार भी इस देश को नहीं बचा पाएगा। संपादकीय में इसे कलयुग की चरम स्थिति बताते हुए कहा गया कि स्वार्थ, अनैतिकता और भ्रष्टाचार सामान्य बात बन चुके हैं। अपने आरोपों के समर्थन में ठाकरे गुट ने कहा कि एक ओर अयोध्या में राम मंदिर के दान और सोने की कथित चोरी की चर्चा देश-दुनिया में हो रही है।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची विजय सरकार

नई दिल्ली। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि बकरीद या किसी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की हत्या न हो। सरकार का तर्क है कि इस फ़ैसले से एक तरह की पूरी पाबंदी लग जाती है,

जिसकी व्यवस्था मौजूदा कानून में नहीं है। अपनी स्पेशल लीव पिटिशन में राज्य ने तर्क दिया है कि हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में व्यापक प्रतिबंध लगाकर मूल जनहित याचिका (पीआईएल) के दायरे का उल्लंघन किया है, जबकि याचिका कोयंबटूर में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गायों की हत्या को रोकने तक ही सीमित थी। यह अपील मद्रास हाई कोर्ट के 27 मई, 2026 के उस फ़ैसले को चुनौती देती है, जो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और वी. लक्ष्मीनारायण की डिवीज़न बेंच ने सुनाया था। तमिलनाडु सरकार के अनुसार, पीआईएल में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे गए थे कि जानवरों को मारने का काम केवल अधिकृत बूचड़खानों में ही हो, न कि सार्वजनिक जगहों पर। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि उसने पहले ही निगरानी बढ़ा दी है।

भाजपा का 50 साल तक सत्ता में बने रहने की ललक

सचिन शर्मा

2019 के लोकसभा चुनावों के ठीक पहले आम आदमी पार्टी और फिर कांग्रेस ने जनता से गुहार लगानी शुरू कर दी थी कि इस बार भाजपा को अगर जनता ने नहीं हराया तो फिर यह पार्टी अगले 50 साल तक सत्ता से नहीं जाने वाली। दरअसल, उनका यह डर यूं ही नहीं था। सितंबर 2018 में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि इस बार अगर हम और जीत गए तो अपने काम की बदौलत अगले 50 साल तक सत्ता में बने रहेंगे। इसके बाद 2019 और फिर 2024 में भी केन्द्र में भाजपा की सरकार बन गई। देश के कई राज्यों में भाजपा की सरकारें लगातार बन रही हैं। कुछ उन राज्यों में भी बन रही हैं जो इससे पहले भाजपा के लिए अनसुलझे थे। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इसका उदाहरण हैं। भाजपा की जीत के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को रोक तो कोई नहीं पा रहा है, हां उसके पैरों तले कई क्षेत्रीय पार्टियां कुचली जरूर जा रही हैं। हाल ही में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का हो हश्र हुआ उससे हरेक व्यक्ति हतप्रभ है। आम आदमी पार्टी के ज्यादातर राज्यसभा सांसद भाजपा में जा मिले। जबकि शिवसेना (यूबीटी) के बचे खुचे सांसद भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में आ गए। उड़ीसा की बीजू जनता दल के भी दो राज्यसभा सांसदों ने पाला बदल लिया। देबाशीष सामंतराय और सुजीत कुमार बीजद से इस्तीफा देकर भाजपा के झंडे तले फिर से राज्यसभा पहुंच गए। तो क्या भाजपा के इस देश व्यापी शासन में धीरे-धीरे क्षेत्रीय पार्टियां दम तोड़ देंगी? और भाजपा 50 साल तक सत्ता में रहने के लिए और क्या करना चाहती है, इसी पर चर्चा करते हैं।

दो दशक पहले तक कहा जाता था कि शासन में लंबे समय तक बने रहना सिर्फ कांग्रेस को ही आता है। कांग्रेस दशकों तक देश और तमाम राज्यों में लगातार सत्ता में बनी रही थी। लेकिन 1995 के बाद उदाहरण बदलना शुरू हो गए। भाजपा की गुजरात में सरकार बनी जो आज 31 साल बाद भी बदस्तूर जारी है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में भी भाजपा 2003 में सत्ता में आई। कमलनाथ सरकार के डेढ़ साल के शासन (दिसंबर 2018 से मार्च 2020) को छोड़ दिया जाए तो भाजपा वहां भी दो दशक से ज्यादा समय से सत्ता में बनी हुई है। कई

राज्यों में इस बीच भाजपा ने लगातार 10-15 साल तक शासन किया। दूसरी ओर केन्द्र में भी 1996 में 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी 1998 और फिर 1999 में फिर चुनकर आ गए और लगभग 6 साल तक केन्द्रीय सत्ता में बने रहे। भाजपा 2014 में फिर से केन्द्र में वापसी करती है और 12 साल बाद आज भी वह सत्ता में है। इन्हीं उदाहरणों से राजनीतिक पंडितों की सोच बदल गई।

6 अप्रैल 1980 को भाजपा के गठन के बाद से कई क्षेत्रीय पार्टियों ने भाजपा का फायदा उठाया। 1989 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जनता दल के मुख्यमंत्री बने थे जिन्हें भाजपा ने ही समर्थन दिया था। इसी उत्तर प्रदेश में 1997 और 2002 में भाजपा के ही समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री बनी थीं। भाजपा के सहयोग से ही बिहार में नीतीश कुमार लगभग दो दशक तक मुख्यमंत्री रहे। भाजपा ने 1999 में जम्मू-कश्मीर की नेशनल कांफ्रेंस को भी एनडीए में शामिल करके उमर अबदुल्ला को केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री बनाया। अबदुल्ला फिलहाल कांग्रेस के साथ गंठबंधन में रहकर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। इतना ही नहीं अपनी धुर विरोधी रही पीडीपी की महबूबा मुफ्ती तक को समर्थन देकर भाजपा ने 4 अप्रैल 2016 को जम्मू-कश्मीर का मुख्यमंत्री बनवा दिया। लेकिन 2019 से भाजपा ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद शिवसेना से मात खाने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली।

महाराष्ट्र में 2019 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद शिवसेना पाला बदलकर एनसीपी-कांग्रेस के साथ चली गई। वहां उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मुख्यमंत्री पद ही भाजपा और शिवसेना में हुए झगड़े की जड़ में था। बस यहीं से कहानी शुरू हो गई। जून 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी। उनके साथ अधिसंख्य विधायक चले गए। भाजपा ने समर्थन देकर शिंदे को मुख्यमंत्री बनवा दिया। बाद में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ही चुनाव आयोग ने असली शिवसेना मान लिया। यही कहानी एनसीपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) के साथ दोहरा दी गई। अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ी, फिर असली एनसीपी उनकी हो गई और वो महाराष्ट्र सरकार में उपमुख्यमंत्री बन गए। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकलने के साथ ही उसका भरभरा कर गिर जाना बताता है कि यह क्षेत्रीय दल भले ही ऊपर से बहुत दिलेर दिखता था लेकिन उसके नेताओं के मन में भाजपा के लिए बहुत डर भरा हुआ था। अब यह तय है कि महाराष्ट्र की तर्ज पर ही तृणमूल कांग्रेस भी ममता बनर्जी के हाथ से निकलकर ऋताब्रत बनर्जी की हो जाएगी और अगले पांच साल तक पश्चिम बंगाल में विपक्ष जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा।

भिलाई में जेएलएन अस्पताल के निजीकरण की चर्चा हुई तेज

भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना साल 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रयासों से हुई थी। भिलाई स्टील प्लांट अपनी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। भिलाई स्टील प्लांट में हजारों की संख्या में लोग काम करते हैं। देश के कोने-कोने से यहां लोग आकर बसे और देश की तरक्की में अपना योगदान दिया। भिलाई स्टील प्लांट को भारत की स्टील सिटी भी कहते हैं। एशिया के बड़े प्लांटों में इसकी गिनती होती है। सोवियत संघ की मदद से इस प्लांट की स्थापना की गई है। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले इसके लिए आधुनिक अस्पताल भी बनाए गए। लेकिन अब अफवाह है कि यहां बने जेएलएन अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। अस्पताल को निजी हाथों में सौंपे जाने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, वैसे ही बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने अस्पताल परिसर के सामने प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रिटायर और कार्यरत कर्मचारियों ने अस्पताल के निजीकरण का विरोध किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों और यूनियन नेताओं ने कहा कि जेएलएन अस्पताल भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों, उनके आश्रितों और सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए एक जीवनरेखा है। ऐसे में इसका निजीकरण हजारों परिवारों के स्वास्थ्य अधिकारों पर सीधा असर डालेगा।

यूनियन नेताओं का कहना है कि पहले भी बीएसपी के स्कूलों के निजीकरण और बंद होने से कर्मचारियों को महंगी शिक्षा का बोझ उठाना पड़ा है। यदि अस्पताल का निजीकरण होता है तो स्वास्थ्य सेवाएं भी महंगी हो जाएंगी और इलाज की गुणवत्ता प्रभावित होगी।

बीएसपी महिला कर्मी सरस्वती ने कहा कि अस्पताल की वर्तमान स्थिति के लिए गलत प्रबंधन और पर्याप्त भर्तियां नहीं होना जिम्मेदार है। वहीं, सेक्टर-9 अस्पताल की डॉ। पार्कर ने कहा कि अस्पताल में आधुनिक मशीनें, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुभवी स्टाफ मौजूद हैं, जरूरत केवल पर्याप्त डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग कर्मियों और तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती की है।

यूनियन ने आरोप लगाया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्थान पर नई नियुक्तियां नहीं की गई है, जिससे अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हुईं।

चिरमिरी में मिलावटी शराब का खेल जारी

चिरमिरी। चिरमिरी शहर में कथित रूप से मिलावटी शराब की बिक्री को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिला उपाध्यक्ष और पूर्व महापौर के. डोमरू रेड्डी ने बड़ा मुद्दा उठाया है। सीएम हेल्पलाईन में शिकायत के बाद जब आबकारी विभाग की टीम ने बताये गये दुकानों पर दबिश दी तो शहर में नकली और मिलावटी शराब से परेशान लोगों में कौतुहल का माहौल देखने को मिला। जनता की ओर से निरन्तर आ रही शिकायत के मद्देनजर कार्यवाही के लिये यह साहस दिखाने वाले कांग्रेस नेता ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि चिरमिरी शहर की कमोबेश सभी देशी और अंग्रेजी शराब दुकानों में वर्षों से मिलावटी शराब का काला कारोबार चल रहा है लेकिन जानकारी होने के बावजूद भी आपसी मिलीभगत के कारण जिम्मेदार विभाग कार्यवाही करने के बजाय मौन रहते हैं। इसमें सत्ताधारी दल के राजनैतिक बिचौलियों की भी बड़ी भूमिका रहती है। अपने शिकायत पर मंगलवार को हुई कार्यवाही के बारे में बात करते हुए पूर्व महापौर के. डोमरू रेड्डी ने बताया कि उन्हें लगातार शराब उपभोक्ताओं से शिकायतें मिल रही थीं कि शराब की गुणवत्ता लगातार खराब है और उसमें कथित रूप से मिलावट की जा रही है। शिकायतों के बाद उन्होंने स्वयं कई शराब दुकानों के आसपास के माहौल का निरीक्षण कर और समय - समय पर शराब खरीददारों से जानकारी एकत्रित किया और फिर पूरे मामले की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में ऑनलाइन दर्ज कराई। जिस पर शिकायत के बाद जांच तो हुई लेकिन किसी भी शराब दुकान या भंडारण स्थल पर मिलावटी शराब नहीं मिली। उनका कहना है कि यदि पहले से सूचना लीक हो जाये तो सबूत मिलना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे मामले में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार और मिलीभगत के कारण प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। हालाकि आबकारी विभाग के जाँच टीम के समक्ष ही डोमनहिल, गोदरीपारा और छोटी बाजार शराब दुकानों में शराब खरीद रहे ग्राहकों से पूछने पर उन्होने टीम को बताया है कि पानी मिला हुआ, पतला शराब बिकता है लेकिन आज जब आप लोग आये हो तो आज तो अच्छा मिलेगा ही। उन्होंने यह भी कहा कि शराब दुकानों में स्थानीय राजनैतिक संरक्षण में प्लेसमेंट एजेंसी के लोगों की नियुक्ति और विभागीय निगरानी व्यवस्था की कमी के कारण गड़बड़ियों की आशंका बनी रहती है साथ ही उन्होंने मांग की कि शराब दुकानों को घनी आबादी और मुख्य सड़क के किनारे संचालित नहीं किया जाना चाहिये और सरकार को इस संबंध में नियमों का सख्ती से पालन कराना चाहिये। के. डोमरू रेड्डी ने राज्य सरकार और आबकारी विभाग से निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराने, दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करने और चिरमिरी में कथित मिलावटी शराब के कारोबार और इनके संरक्षण से गली मोहल्ले में बेधड़क बिक रहे शराब पर स्थायी रोक लगाने की माँग की है।

किसानों को मिलेगा भूमि अधिग्रहण मुआवजा

बिलासपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग-130 (बिलासपुर-कटघोरा मार्ग) के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा विवाद में जिला अदालत ने किसानों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने ग्राम मेलनाडीह के महेश, कार्तिक और रेखा की दायर याचिका स्वीकार करते हुए साल 2018 में पारित मुआवजा अवार्ड के अनुसार 26 लाख 63 हजार 199 रुपए की मुआवजा राशि निर्धारित ब्याज सहित 45 दिनों के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

मामला राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के निर्माण के लिए अधिग्रहित खसरा नंबर 61/4 की 0.061 हेक्टेयर भूमि से जुड़ा है। साल 2018 में उस भूमि के लिए आवेदकों के पक्ष में मुआवजा स्वीकृत किया गया था, लेकिन बाद में प्रताप सिंह नेताम ने भूमि और मकान पर अपना दावा प्रस्तुत करते हुए मुआवजा भुगतान पर आपत्ति दर्ज कराई थी।

सुनवाई के दौरान आवेदकगणों की ओर से अधिवक्ता नेल्सन पन्ना ने पक्ष रखा इसके बाद न्यायालय ने राजस्व अभिलेख, जांच रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण किया। न्यायालय ने पाया कि संबंधित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आवेदकों के नाम दर्ज है।वहीं प्रतिवादी अपने स्वामित्व का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। न्यायालय ने यह भी माना कि अवार्ड जारी होने के लगभग नौ माह बाद आपत्ति दर्ज की गई, जो तथ्यों के अनुरूप नहीं थी।

बलरामपुर में किसानों ने किया कलेक्ट्रेट घेराव

फर्जी केसीसी की जांच और धान के लंबित भुगतान की मांग

किसानों का कहना है कि उन्होने कोई भी लोन बैंक से नहीं लिया जबकि बैंक का कहना है कि उनके ऊपर लोन है.

बलरामपुर। मंगलवार को किसानों ने जोरदार प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। किसान रामचंद्रपुर विकासखंड के अंतर्गत सहकारी बैंक से फर्जी केसीसी लोन की समस्या और लंबित धान बिक्री की राशि जारी करने की मांग कर रहे थे। किसानों ने संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर समर्थन मूल्य पर बेची गई धान की राशि जारी करने एवं उनके नाम पर गलत तरीके से निकाले गए फर्जी केसीसी लोन प्रकरणों का जल्द निराकरण करने की जल्द से जल्द मांग की।किसानों ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव कर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है की उनके नाम से फर्जी तरीके से सहकारी बैंक से लोन निकाली गई है, जिसके कारण उन्हें समर्थन मूल्य पर बेची गई धान की राशि आज तक नहीं मिल पाई है। रामचंद्रपुर विकासखंड के 50 से अधिक किसान समर्थन मूल्य पर बेची गई धान की रकम की मांग कर रहे हैं। किसानों का आरोप है सहकारी बैंक में उनके नामों पर फर्जी तरीके से लोन ली गई थी जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। उनके बैंक खाते होल्ड कर दिए गए हैं।

धमतरी जिले को मिली शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात

धमतरी। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने तथा जनजातीय विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में धमतरी जिले को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जिले में एक नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नवीन संस्थान के प्रारंभ होने से जिले के दूरस्थ, वनांचल एवं दुर्गम क्षेत्रों के प्रतिभावान जनजातीय छात्र-छात्राओं को उत्कृष्ट, आधुनिक एवं पूर्णत: नि:शुल्क आवासीय शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि जिले के नगरी विकासखंड अंतर्गत पथररीडीह में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अपनी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों, अनुशासित शिक्षण व्यवस्था, अत्याधुनिक अधोसंरचना तथा खेल एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों में उल्लेखनीय प्रदर्शन के कारण प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ मॉडल विद्यालयों में अपनी पहचान बना चुका है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन तथा क्षेत्रीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा जिले में दूसरे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है।नवीन विद्यालय के प्रारंभ होने से जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ आधुनिक डिजिटल कक्षाएं, विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, खेल सुविधाएं तथा व्यक्तित्व विकास के विविध अवसर उपलब्ध होंगे। चयनित छात्र-छात्राओं को पूर्णत: निरूशुल्क आवास, पौष्टिक भोजन, गणवेश, अध्ययन सामग्री, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी समान अवसर प्राप्त होंगे। विद्यालय में नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ NEET JEE CLAT सहित अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष अकादमिक मार्गदर्शन, अनुभवी शिक्षकों का सहयोग तथा कैरियर काउंसिलिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा एवं प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

दशकों बाद बदल रही अबूझमाड़ की तस्वीर

कभी माओवादियों का सुरक्षित ठिकाना था

बिनागुंडा, जनप्रतिनिधि भी इलाके में जाने से भय खाते थे

कांकेर। बिनागुंडा अबूझमाड़ का वो इलाका है जो दुर्गम जंगल और पहाड़ों के बीच बसा है। कभी माओवादियों की यहां तूती बोला करती थी। गोलियों और बमों की आवाज से ये पूरा इलाका गूंजता था। लेकिन अब तेजी से तस्वीर यहां की बदल रही है।

इलाके में सड़क बनाने का काम शुरू हो चुका है। शासन की कोशिश है कि जल्द से सड़कों को निर्माण कार्य पूरा कर इलाके को विकास से जोड़ा जाए।

जिस बिनागुंडा में कभी पैदल जाने तक की कोई जनप्रतिनिधि हिम्मत नहीं करता था, आज उस बिनागुंडा में बाइक पर बैठकर कांकेर सांसद ग्रामीणों से मिलने पहुंचे हैं। बिनागुंडा के लोगों ने जब कांकेर सांसद को अपने बीच में देखा तो उनको सहज विश्वास नहीं हुआ कि कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने उनके ही गांव में आया है।

ग्रामीणों ने कांकेर सांसद भोजराज नाग का भव्य स्वागत किया। कांकेर सांसद ने बताया कि वो उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर आज उनके गांव तक पहुंचे हैं, ये विश्वास दिलाने कि आने वाले दिनों में इन इलाकों का भी तेजी से विकास होगा। लोगों ने सांसद से मिलकर अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा किए जाने की मांग रखी।

सांसद ने माओवादी हिंसा में मारे गए मनेश नूरुटी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।आदिवासी महिला पुनाय नूरुटी ने अपने पति को निर्दोष बताते हुए नक्सली प्रकरण में जेल भेजे जाने की शिकायत की और न्याय की मांग उठाई।

गांव की अन्य महिलाओं ने भी जेल में बंद आदिवासियों के मामलों की निष्पक्ष समीक्षा की मांग की।

सांसद ने सभी ग्रामीणों की शिकायतें सुनी और विश्वास दिलाया कि उनको हर वो बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जिसके वो हकदार हैं।हालांकि बिनागुंडा में माहौल बदलता नजर आ रहा है, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

आपरेशन सेफ पैसेज के तहत बाघ की खाल व तस्कर गिरफ्तार

कांकेर। कांकेर जिले में वन विभाग को वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन सेफ पैसेज के तहत दो आरोपियों को बाघ की खाल के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपये मूल्य की दो बाघ की खाल और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वन विभाग की टीम ने सोमवार रात करीब 12 बजे पश्चिम बांदे वन परिक्षेत्र के पीवी-78 जनकपुर चौक में घेराबंदी कर दो संदिग्धों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी बाबूराव मडावी और बिजेश्वर गेडाम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के आहेरी थाना क्षेत्र के निवासी हैं। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से दो बाघों की खाल बरामद की गई, जिन्हें जांच के लिए रायपुर भेजा गया है। भानुप्रतापपुर पश्चिम वन मंडल के डीएफओ नवीन कुमार ने बताया कि परसो रात में पखांजूर इलाके में बाइक सवार दो लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 2 बाघ के खाल बरामद की गई है।

ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े लूट की कोशिश नाकाम

कटघोरा। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छुरी में आज दोपहर उस समय सनसनी फैल गई जब दिनदहाड़े नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने राज ज्वैलर्स को निशाना बनाया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार, आज करीब 1 बजे तीन नकाबपोश लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान में घुसे थे। इनमें से एक आरोपी महिला की वेशभूषा (सलवार सूट) में था, जिससे वे किसी को शक न हो। लुटेरों ने सोने की अंगूठी दिखाने के बहाने दुकान संचालक को निशाना बनाया और अचानक मिर्ची पाउडर आंखों में फेंक दिया। इसके बाद आरोपियों ने कट्टा और चाकू की नोक पर दुकान में रखे जेवरात लूटने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने असली के साथ-साथ कुछ नकली जेवरात भी लूट लिए। घटना के समय दुकान में तीन कर्मचारी मौजूद थे। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने संचालक राजकुमार अग्रवाल पर हमला कर दिया।

जेबीसीसीआई-12 के गठन की मांग तेज, कोल इंडिया में बड़े आंदोलन की तैयारी

कोरबा। 1 जुलाई को गेवरा परियोजना में संयुक्त मोर्चा एचएमएस, एटक, इंटक, सीटू ने गेट मीटिंग और धरना प्रदर्शन किया। हजारों विभागीय और ठेका श्रमिकों ने कोल इंडिया प्रबंधन से जेबीसीसीआई-12 का तुरंत गठन करने की मांग की। हिन्द खदान मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की। यह दिन मांग दिवस के रूप में मनाया गया। गेट मीटिंग में वक्ताओं ने बताया कि पिछला वेतन समझौता लागू हुए काफी समय हो चुके हैं। नए वेतन समझौते के लिए जेबीसीसीआई-12 का गठन अब तक नहीं हुआ है। कमेटी के बिना वेतन समझौता वार्ता शुरू नहीं हो सकती। इससे कर्मचारियों को रिवाइज्ड वेतन समय पर नहीं मिलेगा। प्रदर्शन के दौरान श्रमिकों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि वेतन बढ़ोतरी और भत्तों में संशोधन की वार्ता शुरू करना उनका हक है। इसमें और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने गेवरा क्षेत्रीय मानव संसाधन प्रबंधक सुधा शिंदे को मांग पत्र सौंपा।

मंकी कैप पहनकर बैंक में चोर कंप्यूटर ले उड़ा

जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम जर्वे स्थित छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में एक बार फिर चोरी की वारदात हुई है। एक अज्ञात नकाबपोश चोर बैंक का ताला काटकर अंदर घुस गया। चोर की पूरी गतिविधि बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी प्रदीप सोरी से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब 3:07 बजे यह घटना हुई। एक अज्ञात युवक मंकी कैप पहनकर बैंक पहुंचा था। बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में वह 3:34 बजे तक दिखाई दिया। आशंका है कि उसने लोहे के रॉड या आरी की मदद से मुख्य गेट का ताला काटा। इसके बाद वह बैंक के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर घुसने के बाद चोर ने सबसे पहले बैंक की लाइट बंद कर दी। ऐसा उसने अपनी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से दिखाई न देने के लिए किया। बुधवार सुबह करीब 10 बजे बैंक कर्मचारी पहुंचे तो मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। आरोपी का चेहरा मंकी कैप से ढका हुआ दिखा।

28 मामलों में वाहनों का पता चला, पांच को भुगतान

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मुकेश रावटे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा इसमें उपस्थित रहे। समिति के अन्य सदस्य भी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। परिवहन विभाग ने जिले में दर्ज हिट एंड रन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत की। अधिकारियों ने बताया कि कुल 28 मामलों में दुर्घटना करने वाले वाहनों का पता लगाया जा चुका है। इनमें पेण्ड्रारोड क्षेत्र के 13 प्रकरण शामिल हैं। पेण्ड्रा क्षेत्र से 8 और मरवाही क्षेत्र से 7 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई कि 6 प्रकरणों में निपटान आयुक्त द्वारा प्रतिकर की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वहीं 5 मामलों में साधारण बीमा परिषद ने दावाकर्ताओं के विधिक प्रतिनिधियों के बैंक खातों में भुगतान कर दिया है। यह भुगतान ई-संदाय के माध्यम से किया गया है।

एमसीबी के सोनवर्षा में राशन वितरण में अनियमितता

अनाज नहीं मिलने से हितग्राही नाराज

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत के ग्राम सोनवर्षा में पीडीएस के तहत राशन वितरण में कथित अनियमितता की शिकायत हुई है। अपने हिस्से का राशन नहीं मिलने से नाराज एक दर्जन से अधिक ग्रामीण, ग्राम पंचायत की सरपंच के नेतृत्व में कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे। नाराज ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।सोनवर्षा के ग्रामीणों का आरोप है कि राशन दुकान में 3 माह का खाद्यान्न उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें केवल 2 माह का ही राशन दिया गया, जबकि 1 माह का राशन अब तक नहीं दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब वो राशन मांगने के लिए जाते हैं तो उनसे गलत भाषा का इस्तेमाल भी किया जाता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपे आवेदन में बताया कि राशन दुकान में 3 महीने का खाद्यान्न आया था, लेकिन हितग्राहियों को केवल 2 महीने का राशन वितरित किया गया। जब शेष एक महीने का राशन मांगा गया तो राशन वितरणकर्ता ने देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, विरोध करने और जानकारी मांगने पर हितग्राहियों के साथ अभद्र व्यवहार और गाली-गलौच तक करने का आरोप है। ग्रामीणों के अनुसार इस कथित अनियमितता से करीब 111 हितग्राही परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें अधिकांश गरीब, मजदूर और राशन पर आश्रित परिवार शामिल हैं। कई बार स्थानीय स्तर पर शिकायत करने के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला, तब ग्रामीण सामूहिक रूप से कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। ग्राम पंचायत की सरपंच ने भी ग्रामीणों के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि गांव के कई परिवारों को निर्धारित राशन नहीं मिला है।

एमसीबी का लाहिड़ी कॉलेज हुआ जर्जर, नए सत्र से पहले भवन मरम्मत की मांग तेज

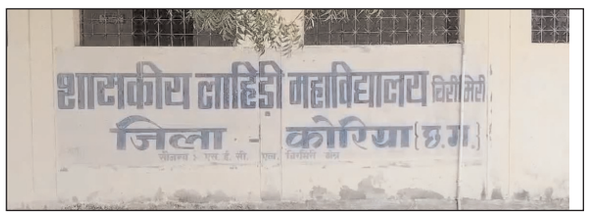

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। चिरमिरी के ऐतिहासिक शासकीय लाहिड़ी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नया शैक्षणिक सत्र 17 जुलाई से शुरू होने वाला है। नए सत्र के शूरू होने से पहले एक बार फिर भवन के मरम्मत की मांग तेज हो गई है। दरअसल, जर्जर भवन के चलते हमेशा हादसों का डर बना रहता है।

छात्रों का कहना है कि कई क्लासों में छतों के प्लास्टर टूट टूटकर गिरते हैं। जबकि दीवारों में भी दरारें है।कॉलेज में करीब एक हजार छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं। कॉलेज में कला, वाणिज्य, विज्ञान, कंप्यूटर सहित स्नातकोत्तर के तीन विषयों और पीजीडीसीए की कक्षाएं संचालित होती हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में यहां पढ़ने पहुंचते हैं। ऐसे में भवन की खराब स्थिति ने छात्रों और प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी है। कला संकाय की इमारत वर्ष 2005 में एसईसीएल के माध्यम से बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में यह भवन जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। दीवारों में कई जगह दरारें हैं और छत का प्लास्टर गिरने की स्थिति में है। बारिश के दौरान कक्षाओं और विभागों में पानी भरने की समस्या भी सामने आती रही है। जर्जर हालत के कारण पहले जहां कला संकाय में 13 कक्षाएं संचालित होती थी, वहीं अब केवल 5 कक्षाएं ही लग पा रही हैं। पिछले सत्र से भवन की स्थिति खराब होने के कारण कई हिस्सों को बंद रखना पड़ा है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा भवन की स्थिति को लेकर संबंधित विभागों को जानकारी दी गई थी। मरम्मत के लिए ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन डेढ़ साल बीतने के बाद भी काम शुरू नहीं हो सका। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन और विद्यार्थियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी समस्या के समाधान की मांग की। पिछले साल कला संकाय की कक्षाएं बरामदे में संचालित करनी पड़ी थी। वर्तमान में जगह की कमी के कारण कुछ कक्षाएं दूसरे विभागों के भवनों में लगाई जा रही हैं। कॉमर्स की कक्षाएं आर्ट्स भवन में और कुछ कक्षाएं सीमित संसाधनों के बीच संचालित हो रही हैं। जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष मनीष खटीक ने कहा कि कॉलेज भवन की हालत लगातार खराब होती जा रही है।

संक्षिप्त समाचार

स्कूलों में मंत्रोच्चार अनिवार्य : शिक्षा मंत्री गजेन्द्र ने कहा- निर्बाध रूप से रहेगा जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार के आदेश को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। आदिवासी संगठन, ईसाई संस्थाओं के साथ कांग्रेस ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस घटनाक्रम के बीच स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ संस्कार देने के उद्देश्य से मंत्रोच्चार कराने का फैसला लिया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई है। शिक्षा गजेन्द्र यादव का कहना है कि फिलहाल सरकारी स्कूलों में निर्बाध रूप से मंत्रोच्चार चलेगा। मामले में कोर्ट जो फैसला सुनाएगी, उसके अनुसार आगे होगा। सरकार अपने आदेश पर कायम है और अदालत का जो भी फैसला आएगा, उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र 2026-27 के दौरान रिटायर होने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। वह पूरे शैक्षणिक सत्र तक पढ़ा सकेंगे। इस फैसले को लेकर शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने बताया कि शैक्षणिक सत्र के बीच अगर कोई शिक्षक रिटायर होता है तो वह सत्र के आखिर तक स्कूलों में पढ़ा सकेगा। हालांकि अगर कोई ऐसा नहीं करना चाहता है, तो यह अलग विषय है, लेकिन ज्यादातर लोगों की इस पर सहमती रहती है।

नगरीय निकायों को महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि के 104.54 करोड़ जारी

रायपुर। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर निगमों में महापौर निधि, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि तथा तीनों तरह के निकायों में पार्षद निधि के रूप में 104 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपए जारी किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने नगरीय निकायों को ये राशि जारी कर दी है। श्री साव ने नगरीय निकायों को इन निधियों का सदुपयोग करते हुए राज्य की शहरी आबादी तक योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस राशि से निकायों में मूलभूत विकास के कार्य किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नगर निगमों में महापौर निधि तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की 50-50 प्रतिशत राशि की प्रथम किस्त के रूप में कुल 31 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपए जारी किए गए हैं। तीनों तरह की नगरीय निकायों में पार्षद निधि के रूप में कुल 73 करोड़ 38 लाख रुपए भी जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा 14 नगर निगमों में महापौर निधि के 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए, 57 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष निधि के 11 करोड़ 6 लाख 25 हजार रुपए तथा 121 नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि के 9 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपए जारी किए गए हैं। वहीं पार्षद निधि के प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में नगर निगमों को 21 करोड़ 84 लाख रुपए, नगर पालिकाओं को 24 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपए एवं नगर पंचायतों को 27 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपए जारी किए गए हैं।

शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक शिक्षकों को मिलेगी पुनर्नियुक्ति

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त शालाओं में कार्यरत शिक्षक संवर्ग (सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक) को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है। मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। आदेश में संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देशित किया गया है कि पुनर्नियुक्ति संबंधी जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान करने की आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर पर शीघ्र सुनिश्चित करें। शासन के इस निर्णय से शासकीय एवं शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई निर्बाध रूप से संचालित हो सकेगी।

नगर पंचायत बम्हनीडीह के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण आज

रायपुर। जांजगीर-चांपा जिले के नगर पंचायत बम्हनीडीह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह 2 जुलाई 2026, गुरुवार को प्रात: 10:30 बजे आई.टी.आई. ग्राउंड, बम्हनीडीह में आयोजित किया जाएगा। समारोह में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री रमेश कुमार डड़सेना तथा सभी नवनिर्वाचित पार्षद पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव करेंगे। जिले के प्रभारी मंत्री एवं वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहेब तथा जांजगीर-चांपा सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंहदेव, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री सौरभ सिंह, जैजैपुर विधायक श्री बालेश्वर साहू, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल, पूर्व संसदीय सचिव श्री अम्बेश जांगड़े तथा जिला पंचायत जांजगीर-चांपा की अध्यक्ष इंजी. सत्यलता आनंद मिरी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं क्षेत्रवासियों की उपस्थित रहेंगे।

'विकसित भारत जी राम जी' योजना पूरे देश में लागू

योजना के तहत श्रमिकों को साल में 125 दिन का काम मिलेगा

रायपुर। 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना लागू हो गई है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका संवर्धन और आधारभूत विकास को नई गति देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत -2047 के विज़न को साकार करने की दिशा में ग्रामीण भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाना है।

विकसित भारत जी राम जी' योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, आजीविका संवर्धन और गांवों के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।

योजना अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को मांग के आधार पर वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जल संरक्षण, ग्रामीण अधोसंरचना विकास, कृषि आधारित कार्य, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका संवर्धन जैसे टिकाऊ कार्यों को प्राथमिकता मिलेगी। विकसित ग्राम की परिकल्पना को साकार करने के लिए योजना में कुल 318 प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2026-27 के बजट में 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ में योजना के शुभारंभ एवं क्रियान्वयन को लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 2 जुलाई 2026 को तिरुपति, आंध्रप्रदेश से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें वे देश के विभिन्न राज्यों से संवाद करेंगे। प्रदेश में यह कार्यक्रम कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गंडईखुर्द में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ग्रामीणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़कर संवाद करेंगे।

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी मिलेगी, 15 दिवस के भीतर मजदूरी भुगतान की व्यवस्था होगी, कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। इसी तरह डिजिटल जॉब कार्ड एवं तकनीक आधारित कार्य प्रबंधन प्रणाली, समयबद्ध एवं पारदर्शी भुगतान व्यवस्था के साथ ग्राम सभा की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाया गया है।

वीबी जीरामजी में जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण सड़क, वृक्षारोपण एवं टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। इस योजना से ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास एवं आजीविका के नए अवसर प्रदान करेगी। सामाजिक अंकेक्षण एवं डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता में भी वृद्धि होगी। नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की कार्ययोजना ग्राम सभा के माध्यम से तैयार की जाएगी, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों का चयन किया जा सकेगा।

विकसित भारत-जी राम जी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और गांवों में विकास की स्थायी आधारशिला तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प से जोड़ने का माध्यम बनेगी।

जिलाध्यक्षों को नमस्ते करेंगे अब कांग्रेस विधायक, इसलिए कि सर्वे रिपोर्ट वही बनायेंगे

रायपुर। कांग्रेस जिलाध्यक्षों का अभनपुर प्रशिक्षण शिविर संगठन के लिहाज से देखें तो उन्हे काफी पावरफुल कर गया। शीर्ष नेतृत्व ने जिलाध्यक्षों को यहां तक पावर दे दिया है कि वे अपने जिलों में कांग्रेस विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। उन्हें जनता के बीच विधायकों की छवि, सक्रियता और जनसंपर्क को लेकर सर्वे कर उसकी रिपोर्ट संगठन को सौंपनी होगी। विधायकों को अब जिलाध्यक्षों के आगे पीछे घूमना होगा अपना रैंकिंग बेस्ट बनवाने के लिए। हालांकि वे खुद भी घेरे में रहेंगे. शिविर के दौरान यह भी तय किया गया कि अब जिला अध्यक्षों के कामकाज का मूल्यांकन रेड, येलो और ग्रीन कैटेगरी में किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रीन कैटेगरी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले, येलो कैटेगरी में सुधार की जरूरत वाले और रेड कैटेगरी में कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिला अध्यक्ष शामिल किए जाएंगे। इसी आधार पर संगठन उनकी कार्यशैली और प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करेगा।

कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर : जहां गांधी परिवार की चरण वंदना का पाठ पढ़ाया गया - चिमनानी

■ राहुल गांधी सिर्फ खानापूर्ति करने आए और मैगी खाकर चले गए!

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कांग्रेस के 10 दिनों तक चले कथित प्रशिक्षण शिविर पर करारा तंज कसते हुए इस शिविर की तुलना बिग बॉस के घर से करते हुए कहा कि यहाँ कार्यकर्ताओं को देश या जनता की सेवा का नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की चाकरी और सेवा करने का प्रशिक्षण दिया गया है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता चिमनानी ने तीखा हमला बोलकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी, जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी प्रशिक्षण शब्द का मतलब तक नहीं समझा, वे खुद कार्यकर्ताओं को ज्ञान बाँटने आ गए! इतना ही नहीं, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पवन खेड़ा और अलका लाम्बा जैसे अप्रशिक्षित लोग वहाँ दूसरों को प्रशिक्षित करने आए या बिगाडने। श्री चिमनानी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी को न तो कार्यकर्ताओं की चिंता थी और न ही प्रशिक्षण से कोई लेना-देना था। वे इस शिविर में केवल

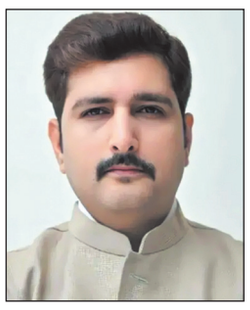

खानापूर्ति करने के लिए आए थे, वहाँ मैगी खाई और वापस चले गए। यह शिविर पूरी तरह से बेअसर और सिर्फ राजनीतिक तमाशा बनकर रह गया।

चिमनानी ने कहा कि देश के गिने-चुने राज्यों तक सिमट चुकी कांग्रेस पार्टी का भविष्य पूरी तरह अंधकारमय है और आने वाले समय में यह भारत के राजनीतिक नक्शे से गायब हो जाएगी। देश की जनता हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा करने वालों को मौका देती है, न कि भ्रष्टाचार के जरिए देश को लूटने वालों को। श्री चिमनानी ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए प्रशिक्षण शब्द का असली अर्थ बेहद सीमित है। उनके लिए इसका मतलब सिर्फ जनता की जेब पर डाका डालकर अपनी जेबें भरना है और एक खास परिवार की परिक्रमा करके पार्टी में अपना नम्बर बढ़ाना है।

आदिवासी हितों से जुड़े विभिन्न विषयों के निराकरण हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश: मुख्य सचिव

■ फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की जांच प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में अनुसूचित जनजाति वर्ग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, रायपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र में बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा उनके निराकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

बैठक में अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा एक्ट, 1996 एवं राज्य के पेसा नियम, 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मैदानी स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर शासकीय सेवा में नियुक्ति अथवा पदोन्नति प्राप्त करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों

के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई, आदिवासी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति संबंधित अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आदिवासियों के हित संबंधित विषयों के समन्वित अध्ययन एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग तथा खनिज विभाग के सचिवों को सदस्य बनाकर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए। उन्होंने कहा कि जाति प्रमाण-पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी एवं सुदृढ़ हो तथा सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। मुख्य सचिव ने आदिवासी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजना को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करने तथा इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

बैठक में आदिम जाति विकास विभाग तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, सामान्य प्रशासन तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री रामविचार नेताम ने किया कृषि महाविद्यालय कुरूद का भ्रमण

आधुनिक शिक्षण एवं अनुसंधान सुविधाओं का लिया जायजा

रायपुर। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज बस्तर प्रवास के दौरान कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कुरूद का भ्रमण कर महाविद्यालय में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्यों तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने आधुनिक कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान को राज्य के कृषि विकास की मजबूत आधारशिला बताते हुए विद्यार्थियों को नवाचार और तकनीक आधारित कृषि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

महाविद्यालय पहुंचने पर अधिष्ठाता डॉ. नवनीत राणा ने मंत्री श्री नेताम का स्वागत किया तथा विभिन्न शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। मंत्री श्री नेताम ने महाविद्यालय की आधुनिक प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और कॉम्पिटिटिव

फोरम का निरीक्षण किया तथा छात्र-छात्राओं से संवाद कर महाविद्यालय एवं छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें अध्ययन एवं आवास से जुड़ी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

भ्रमण के दौरान मंत्री श्री नेताम ने कृषि संग्रहालय में छात्र-छात्राओं द्वारा तैयार कृषि मॉडल, प्रदर्शनी और मशरूम प्रसंस्कृत उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यार्थियों की नवाचारी सोच और महाविद्यालय में उपलब्ध आधुनिक सुविधाओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की तथा छात्र-छात्राओं के साथ कृषि क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते उपयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में किए गए नवाचारों पर विस्तृत चर्चा की।

भ्रमण कार्यक्रम में धमतरी कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद, महाविद्यालय के प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

मंत्रालय के तीन अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानपूर्ण विदाई

मंत्री देवांगन ने स्मृति चिन्ह भेंट कर दी शुभकामनाएं

रायपुर। राज्य शासन की सेवा में दीर्घकाल तक योगदान देने के उपरांत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए तीन अधिकारी-कर्मचारियों के सम्मान में आज मंत्रालय महानदी भवन में सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके स्वस्थ, सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सेवानिवृत्त होने वालों में श्रम विभाग के अवर सचिव श्री कीर्तिवर्धन उपाध्याय, गृह विभाग के स्टाफ ऑफिसर श्री राजेश हीरा तथा स्कूल शिक्षा विभाग के दफ्तरी श्री चौनसिंह शामिल हैं। इस अवसर पर मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के साथ निभाई गई शासकीय सेवा सदैव प्रेरणादायी होती है। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का योगदान शासन-प्रशासन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों के स्वस्थ, सुखद एवं सम्मानपूर्ण जीवन तथा उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। समारोह में मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

गरीबों के घर तोड़कर हम चैन की नींद नहीं सो सकते पीड़ितों के लिए हम कोर्ट तक जाएंगे: दीपक बैज

रायपुर। नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर गरीब, आदिवासी और वंचित परिवारों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। बैज ने सवाल उठाया कि क्या गरीबों के आशियाने उजाड़कर विधायकों, अफसरों और प्रभावशाली लोगों के लिए आवास बनाए जाएंगे ? कांग्रेस ने सरकार से माफी, मुआवजा और पुनर्वास की मांग करते हुए साफ चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो मामला अदालत से लेकर विधानसभा तक गूंजेगा।

दीपक बैज ने कहा कि नकटी गांव में 85 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, जिनमें करीब 25 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे। उन्होंने इसे अमानवीय, अनैतिक और गैरकानूनी कार्रवाई बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार गरीबों के घर तोड़कर आईएएस, आईपीएस अधिकारियों और विधायकों के लिए आवास बनाना चाहती है।

दीपक बैज ने कहा कि जिन परिवारों के घर तोड़े गए, उन्हें बिना पर्याप्त व्यवस्था के ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में भेजा गया है। बैज ने आरोप लगाया कि वहां बिजली, पानी, पंखा और खिड़की जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। उन्होंने मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वे दो घंटे उन फ्लैटों में रहकर देखें और बताएं कि चौथी मंजिल पर बुजुर्ग और छोटे बच्चे कैसे रहेंगे।

पीसीसी चीफ ने कहा कि आदिवासी विधायक जनक ध्रुव और विधायक चातुरी नंद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि उन्हें गरीबों के घर तोड़कर बनने वाला विधायक आवास नहीं चाहिए। बैज ने दोनों विधायकों का धन्यवाद देते हुए सभी विधायकों से ऐसे आवास का बहिष्कार करने की अपील की। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार अपनी गलती स्वीकार करे, पीड़ित परिवारों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, प्रभावितों को उसी स्थान पर जमीन देकर बसाए और उनके नुकसान की भरपाई करे। साथ ही यह भी स्पष्ट करे कि जिनके प्रधानमंत्री आवास और इंदिरा आवास तोड़े गए हैं, क्या उन्हें दोबारा इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। दीपक बैज ने सवाल उठाया कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक अनुज शर्मा अंतिम समय तक लोगों को मकान नहीं टूटने का भरोसा दिलाते रहे। ऐसे में क्या सरकार ने अपने ही जनप्रतिनिधियों को गुमराह किया, या फिर लोगों को झूठा आश्वासन देने के पीछे कोई सुनियोजित रणनीति थी। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार ने यह कार्रवाई भाजपा से जुड़े लोगों और कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की है। उन्होंने मांग की कि पूरे इलाके का निष्पक्ष सीमांकन कराया जाए और यह सार्वजनिक किया जाए कि आसपास की जमीन पर किसका कब्जा है।

दीपक बैज ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। पार्टी पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएगी और विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में भी इस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाएगी।

कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, बालोद
उप वनमण्डल, जिला-बालोद (छ.ग.)

सागोन काष्ठ को शासन की सम्पति घोषित किए जाने की सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, वन परिक्षेत्र बालोद अंतर्गत दिनांक 02.02.2026 को परिसर रक्षक मालगांव को अज्ञात व्यक्ति की सूचना के आधार पर ग्राम मड़वापथरा से मालगांव मार्ग में नाला के पास आग लगे हुए खेत में राष्ट्रीयकृत वनोपज सागोन प्रजाति लट्ठा 03 नग = 0.195 घ.मी. काष्ठ पाया गया, जिसके फलस्वरूप परिसर रक्षक मालगांव द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 60/03 दिनांक 02.02.2026 पंजीबद्ध किया गया है।

उक्त काष्ठ छ.ग. ईमारती लकड़ी (बहती हुई, किनारे अटकी हुई, बिना स्वामी की) नियम, 1986 के नियम 3 अनुसार पाए जाने पर राज्य शासन की सम्पत्ति घोषित किए जाने के संबंध में कार्यवाही अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में विचाराधीन है। सागोन काष्ठ मालिक / हितबद्ध व्यक्ति को इस सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डल बालोद (काष्ठागार परिसर बालोद) में कार्यालयीन समय में सागोन काष्ठ के संबंध में अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करें, समयावधि समाप्त होने के पश्चात् एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये सागोन काष्ठ को शासन की सम्पत्ति घोषित की जावेगी।

दिनांक 17.06.2026

उप वनमण्डलाधिकारी,
बालोद उप वनमण्डल, बालोद

जी-262701752/3

भारत-ईयू ऊर्जा सहयोग और प्राथमिकताएं

अपर्णा रॉय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप का दौरा ऐसे समय में किया, जब ऊर्जा सुरक्षा भू-राजनीतिक मुद्दे पर वापस आ गई है। यूक्रेन में युद्ध ने यूरोप की आयातित फ्यूल पर निर्भरता को सामने ला दिया है। पश्चिम एशिया में हाल ही में संघर्ष में वृद्धि ने एक बार फिर वैश्विक ऊर्जा प्रवाह की नाजुकता को दिखाया है। साथ ही, बैटरी, महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा सप्लाई चेन को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। भारत और यूरोप दोनों के लिए, ऊर्जा परिवर्तन अब मात्र एक जलवायु परियोजना नहीं रह गया है। यह आर्थिक सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीतिक लचीलेपन का एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। फिर भी, भारत-यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी का बड़ा हिस्सा पहले समय की प्राथमिकताओं पर ही केंद्रित है, जैसे- नवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार, तकनीकी हस्तांतरण, और जलवायु महत्वाकांक्षा। इन उद्देश्यों का महत्व बना हुआ है, लेकिन आज दोनों पक्षों (भारत और यूरोप) के सामने मुख्य चुनौती नवीकरणीय ऊर्जा का एक और गीगावाट जोड़ना नहीं है। चुनौती यह है कि इसके बाद क्या होगा। क्या भारत एक ऐसी बिजली प्रणाली का निर्माण कर सकता है, जो बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा को सुचारू और भरोसेमंद तरीके से ग्रिड में एकीकृत कर सके? क्या यूरोप अपनी औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को कम किए बिना खुद को कार्बन-मुक्त कर सकता है? क्या दोनों महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकों और पूंजी को लेकर नई रणनीतिक निर्भरता बनाए बिना जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं? इन सवालों से भारत-ईयू सहयोग का अगला चरण तय होना चाहिए। भारत का ऊर्जा परिवर्तन अब तेज उत्पादन से कहीं अधिक एकीकरण की समस्या से बाधित हो रहा है। सौर ऊर्जा का उत्पादन दिन के समय चरम पर होता है, जबकि बिजली की मांग सूरज डूबने के बाद बढ़ती है। नवीकरणीय ऊर्जा से संपन्न क्षेत्र अक्सर औद्योगिक केंद्रों से दूर होते हैं। मई और दिसंबर 2025 के बीच, भारत ने लगभग 2.3 TWh (टेरावाट-घंटे) नवीकरणीय बिजली की कटौती की, जो स्वच्छ ऊर्जा को पूरे सिस्टम में भेजने और उसे संतुलित करने में बढ़ती बाधाओं को उजागर करता है। चुनौती अब नवीकरणीय बिजली बनाना नहीं है। बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि बिजली उपभोक्ताओं तक तब और वहां पहुंचे, जब और जहां इसकी जरूरत हो। इसके लिए उन्नत ग्रिड मैनेजमेंट, पूर्वानुमान प्रणाली, संतुलन बाजार, भंडारण एकीकरण और मांग-प्रतिक्रिया तंत्र जैसी क्षमताओं की जरूरत है। यूरोप ने इन संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने में कई दशक लगाए हैं। इसलिए सहयोग के अगले चरण को नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार से आगे बढ़कर पूर्ण विद्युत-प्रणाली के कायाकल्प की ओर बढ़ना चाहिए। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के पूर्वानुमान, सहायक सेवाओं और संतुलन बाजारों के क्षेत्रों में भारतीय ग्रिड ऑपरेटरों और उनके यूरोपीय सहयोगियों के बीच साझेदारी शामिल हो सकती है; इसके साथ ही भंडारण-आधारित खरीद और लचीलेपन के तंत्र पर नियामक सहयोग; तथा राजस्थान और गुजरात जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से समृद्ध राज्यों में संयुक्त प्रदर्शन परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं। जैसे-जैसे भारत उच्च नवीकरणीय बिजली सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, परिवर्तनशील बिजली को एकीकृत करने, जमाव का प्रबंधन करने और सिस्टम की पर्याप्तता बनाए रखने में यूरोप के अनुभवों से सीखे गए सबक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जितने ही मूल्यवान साबित हो सकते हैं। ऊर्जा परिवर्तन को तेजी से औद्योगिक नीति द्वारा आकार दिया जा रहा है।

नागरिकता के दस्तावेजों पर इतना भ्रम ठीक नहीं...

उमेश चतुर्वेदी

सरकारी नीतियों ने भी आम आदमी के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान किया

पिछले कुछ वर्षों में पासपोर्ट हासिल करना आसान हो गयाहै। इसकी वजह तकनीकी क्रांति तो है ही, लेकिन सरकारी नीतियों ने भी आम आदमी के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान किया है। पासपोर्ट हासिल करने के कठिन दौर से लेकर आसानी से प्राप्त होने के मौजूदा दौर में, आम नागरिक इसे अपनी नागरिकता का एक वैध दस्तावेज मानता रहा है। लेकिन पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर भारतीय विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के पासपोर्ट को लेकर दिए बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। इस अधिकारी के मुताबिक, भारतीय पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा के लिए एक दस्तावेज है, भारतीय नागरिकता का सबूत नहीं। जहां पासपोर्ट हासिल करने को चार धाम यात्रा जैसी उपलब्धि माना जाता रहा हो, जहां किसी व्यक्ति की पहचान के लिए मजबूत सरकारी सरकारी दस्तावेज द माना जाता रहा हो, वहां ऐसा बयान आएगा तो विवाद होगा ही। तो विवाद हो रहा है। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट नागरिकता का वैध दस्तावेज नही है तो फिर कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता के लिए क्या सबूत पेश करे। भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के शब्दों से गुजरें तो विदेश मंत्रालय के अधिकारी का कहना गलत भी नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में मतदाता सूचियों के विशेष और गहन परीक्षण के दौरान जब घोषित कर दिया गया कि किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र होना उसकी नागरिकता के सबूत नहीं है और अब पासपोर्ट भी नहीं रहा, तो फिर भारतीय नागरिक क्या करे। जरूरत पड़ने पर वह कैसे साबित करे कि वह भारतीय नागरिक है। इस आधार पर तो देश के ज्यादातर लोग अपनी नागरिकता को तो साबित ही नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज के दौर की तमाम लड़ाइयों का बुनियादी और मजबूत आधार चूंकि नैरेटिव बन गया है तो यह भी साबित करने की कोशिश होगी कि मोदी सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया किया है। है इसके लपेटे में मोदी समर्थक ताकतें भी आएंगी, भारतीय जनता पार्टी पर तो खैर सवाल उठेगा ही। इस नैरेटिव को खड़ा होने से पहले ही जरूरी है कि नागरिकता के वैध दस्तावेज को लेकर जारी भ्रम को जल्द से जल्द दूर किया जाए। अन्यथा भ्रम का यह कुहासा जितना फैलेगा, वह आम नागरिक के मन में व्यवस्था के प्रति गुस्सा और क्षोभ भरेगा। इससे तनाव बढ़ाने वाली ताकतों को भी मौका मिलेगा। पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने जो कहा है, वह गलत भी नहीं है। अपने देश में भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत जारी किया जाता है। जबकि भारत में नागरिकता की व्याख्या और प्रमाणिकता के लिए भारतीय नागरिकता कानून 1955 है। पासपोर्ट एक्ट की धारा 20 के मुताबिक, अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी ऐसे व्यक्ति को भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है। बस शर्त यह

के होगी कि सरकार को ऐसा लगे कि उसके लिए पासपोर्ट जारी करना व्यापक जनहित में जरूरी है। इस कानून से साफ है कि पासपोर्ट और नागरिकता दो अलग अलग चीजें हैं। बेशक भारतीय पासपोर्ट सिर्फ भारतीयों को ही मिलता है, लेकिन यह पत्थर की लकीर जैसा नियम नहीं है। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 20 भारत सरकार को छूट देती है कि व्यापक जनहित में वह भारतीय नागरिक ना होने के बावजूद किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी कर सकती है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी के बयान पर भले ही विवाद खड़ा हुआ हो, लेकिन पासपोर्ट के जरिए नागरिकता प्रमाणित करने के तीन अभियुक्तों समेत चार लोगों के दावे को बांबे हाईकोर्ट 2013 में ही खारिज कर चुका है। उन्होंने अपनी नागरिकता लिए पासपोर्ट पेश किया था। बांबे हाईकोर्ट ने दो सितंबर 2013 के अपने फैसले में साफ कर दिया था कि अगर आपका जन्म 1987 के बाद हुआ है तो पासपोर्ट को अपनी नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं पेश कर सकते। वैसे आधार कार्ड का कानून भी मानता है कि आधार कार्ड सिर्फ निवास और पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। आधार कानून 2016 की धारा में साफ लिखा है कि आधार कार्ड से नागरिकता की बजाय सिर्फ निवास स्थान और पहचान प्रमाणित होता है। इसकी वजह यह है कि कानून के तहत 182 दिनों तक भारत में लगातार रहने वाले व्यक्ति को सरकार चाहे तो आधार कार्ड जारी कर सकती है। इसी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय भी इसे नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार कर चुका है। इसी तरह पैन कार्ड के लिए भी व्यवस्था दी गई है। पैन कार्ड का कानूनी आधार है कि व्यक्ति अर्जन कर रहा है और टैक्स दे रहा है। आधुनिक विश्व व्यवस्था की एक खामी यह है कि यहां कानून की भाषा अलग होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कानूनी भाषा जटिल होती है और उसके शब्द जाल को आम आदमी नहीं समझ पाता। इसी आधार पर उसकी अवधारणाएं विकसित होती हैं और फिर वह किसी विषय का व्यवस्था को लेकर अपनी राय बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी को इन जटिलताओं की समझ है, शायद यही वजह है कि उनके आधार

कार्यकाल में देश के सैकड़ों गैरजरूरी कानूनों को या तो रद्द किया गया है या फिर कुछ नए संदर्भों वाले कानूनों में समाहित कर दिया गया है। आज के दौर में नागरिकता के दस्तावेज के रूप जब पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र को आखिरी और अंतिम प्रमाण मानने से इनकार किया जाता है तो अपनी लोक और आम धारणा के चलते आम आदमी इसके विरोध में उतर आता है। यही वजह है कि जब मतदाता सूचियों के विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर के दौरान इन दस्तावेजों को आखिरी दस्तावेज मानने से इनकार किया गया तो इसका विरोध शुरू हुआ था। कुछ इसी अंदाज में पासपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के अधिकारी के बयान पर भी विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पूछ लिया है कि पासपोर्ट बनाने से पहले पुलिस जब व्यक्ति का सत्यापन करती है तो आखिर वह किसका सत्यापन करती है और क्यों करती है? उनका यहां तक कहना है कि इससे लोगों के मन में यह भी संदेह उत्पन्न हो सकता है कि गैर भारतीयों को भी पासपोर्ट दिए जा रहे हैं? इन पंक्तियों के लिखे जाने तक भारत सरकार की ओर से नगारकिता के प्रमाण को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब पासपोर्ट मान्य नहीं, मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड पर भरोसा नहीं और पैन कार्ड मान्य नहीं तो फिर आम नागरिक अपनी नागरिकता को कैसे साबित करे। निश्चित तौर पर इसका भी सरकारी व्यवस्था में है। 20 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में भारत सरकार के प्रवक्ता ने कहा था, %जन्म की तारीख और जन्म-स्थान से जुड़े कोई भी दस्तावेज जमा करके नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि, ऐसे स्वीकार्य दस्तावेजों पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।% इसमें रिलीज में कहा गया था कि जन्म की तारीख और जन्म स्थान से जुड़े कोई भी दस्तावेज जमा करके नागरिकता साबित की जा सकती है। हालांकि, इन दस्तावेजों के बारे में आखिरी रूप से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसमें वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार, लाइसेंस, इंश्योरेंस के कागजात, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जमीन या घर से जुड़े दस्तावेज या सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए भी गए ऐसे ही अन्य दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। इस लिस्ट में और दस्तावेज शामिल किए जा सकते हैं ताकि किसी भी भारतीय नागरिक को बेवजह परेशानी न हो। बेशक कानून की भाषा अलग होती है और लोक का शब्द संसार अलग, लेकिन दोनों के बीच संतुलन होना ही चाहिए। लोक की समझ अपने तंत्र के लिए बेहतर बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि लोक और कानून की भाषा के बीच के अंतर को पाट लिया जाए। अन्यथा गलतफहमियां होती रहेंगी और आखिरकार इससे नुकसान लोकतंत्र का होगा।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

(ञ) हम सौ वर्ष तक जीवित रहें ओर सौ वर्ष से अधिक काल तक जीवित रहें। (ट) [हे नचिकेत! तू स्वयं जितने वर्ष जीना चाहे जी।

आयुष्य पर मनुष्य का अधिकार

हिन्दू साहित्य का मनन करने पर यह बात निश्चित हो जाती है कि एक हद तक मनुष्य ही अपना भाग्यविधाता आप है। यदि वह चाहे तो योगशास्त्र तथा आयुर्वेदशास्त्र निदिष्ट आयुष्यद्धंक उपायों का अवलम्बन करके अपनी आयु को यथेच्छ बढ़ा सकता है।

मनुष्य दीर्घायु हो सकता है! चिरंजीवी हो सकता है!! और अजर अमर भी हो सकता है!!! हिन्दू सिद्धान्त में मनुष्य के लिये मरना कुछ आवश्यक नहीं है, किन्तु वह उसकी इच्छा पर निर्भर है, बशर्ते कि मनुष्य त्रिकालदर्शी महर्षियों द्वारा निर्धारित धर्ममार्ग में पूरी तरह से तत्पर हो। हम अपने इन विचारों का समर्थन करने वाले कुछ वेदप्रमाण नीचे अङ्कित करते हैं जिनसे कि न केवल दीर्घजीवी होने का बल्कि मौत को जीत लेने का भी मानव अधिकार व्यक्त होता है, यथा-

(क) द्राघीयो हि देवायुषम् ।
(शतपथ 7 I3 I1 I10)

(ख) अमृता देवाः ।
(शतपथ 2 I1 I3 I4)

(ग) ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत ।
(अथर्व 11 I5 I16)

(घ) अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्।
आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युविप्राञ्झिघांसति।।
(मनु 5 I4)

अर्थात्- (क) देवताओं की आयु बहुत दीर्घ होती है

(ख) देवता अमर होते हैं।

क्रमशः ...

मोहम्मद अजीज

अनन्या मिश्रा

आज ही के दिन यानी की 02 जुलाई 1954 को हिंदी सिनेमा के दिग्गज गायक मोहम्मद अजीज का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनकी गिनती हिंदी सिनेमा के दिग्गज गायकों में की जाती है। बता दें कि गायक ने अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और सनी देओल जैसे सुपरस्टार्स के फिल्मों में अपनी आवाज दी है। भले ही आज गायक हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनके द्वारा गाए गानों को लोग गुनगुनाना पसंद करते हैं। वह 80 के दशक के बड़ी हिट फिल्मों का हिस्सा रहे।

मोहम्मद अजीज एक ऐसे सिंगर के रुप में जाने जाते हैं, जिसे हिंदी के साथ-साथ बंगाली और उड़िया फिल्मों में गाने का रिकॉर्ड बनाया। मोहम्मद अजीज को अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म 'मर्द' के गाने 'मर्द तांगेवाला' ने मशहूर किया, और ये मौका उन्हें इस फिल्म के संगीतकार अनु मलिक ने दिया था। इस गाने के बाद तो अजीज संगीत की दुनिया के चर्चित गायक में शुमार हो गए।

वह रेडियो पर अक्सर गानें सुना करते थे और वह मोहम्मद रफी के गानों को सुनना पसंद करते थे। वह मोहम्मद अजीज रफी के गाने ऐसे सुनते थे, जैसे मरफी रेडियो के विज्ञापन का मुन्ना दिखता था। इसी कारण उनको बचपन में सब लोग प्यार से मुन्ना कहकर बुलाते थे। तभी तमाम गानों के क्रेडिट में मुन्ना अजीज ही लिखा मिलता है।

बचपन से संगीत में विशेष रुचि रखने वाले अजीज ने कोलकाता में संगीत की ट्रेनिंग ली। वह पारिवारिक और सामाजिक आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। मोहम्मद अजीज को बतौर गायक रेस्टोरेंट में गाना गाने का मौका मिला। तभी उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता से मुलाकात हुई और उनको बंगाली फिल्म ज्योति में गाना गाने का मौका मिला। इस फिल्म में संगीत देने के बाद वह संगीत की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए मुंबई चले आए।

साल 1970 में मोहम्मद रफी पुनर्खोज के दौरान एक अच्छे सिंगर को साइन करने के लिए संगीत निर्देशकों में होड़ लगी थी। उस दौरान रफी गले की बीमारी से परेशान थे। जिसकी वजह से उनका सिंगिंग का काम कुछ समय के लिए रुक गया था। साल 1980 में मोहम्मद रफी की मृत्यु के बाद संगीत निर्देशक उनके जैसा गायक खोज रहे थे। इसी दौरान मोहम्मद अजीज आए और संगीत की दुनिया में अपनी आवाज का जादू बिखेरा।

कुछ ही समय में वह अपनी आवाज के कारण लोगों के दिलों पर छा गए। साल 1984 में उनको फिल्म अम्बर में गाना गाने का मौका मिला। इसी दौरान फिल्म निर्देशक मनमोहन देसाई का अजीज पर ध्यान गया। फिर उन्होंने अजीज की मुलाकात अनु मलिक से करवाई। इस मुलाकात के बात उनको फिल्म मर्द में गाना गाने का मौका मिला। फिल्म के टाइटल ट्रैक के कारण वह लोगों के दिलों पर छा गए। मोहम्मद अजीज ने कई सुपरहिट फिल्मों जैसे त्रिदेव, आदमी खिलौना है, चालबाज आदि में गाने गाए। वहीं 27 नवंबर 2018 को महज 64 साल की उम्र में मोहम्मद अजीज का निधन हो गया।

दक्षिण एशिया से सेशल्स तक : भारत की अंतरिक्ष कूटनीति

अरुणिम भूयान

अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को एक कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की भारत की बढ़ती कोशिशों को रविवार (28 जून) को एक और बड़ी कामयाबी मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के बीच विक्टोरिया में हुई द्विपक्षीय शिखर बैठक के बाद, दोनों देशों ने बाहरी अंतरिक्ष (आउटर स्पेस) के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ठीक उसी मॉडल पर आधारित है, जिसका भारत ने संचार, आपदा प्रबंधन, टेलीमेडिसिन (दूरदराज के इलाकों में चिकित्सा) और शिक्षा के क्षेत्र में सैटेलाइट-आधारित सेवाएं देकर पूरे दक्षिण एशिया में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है।

अपने मित्र देशों को आधुनिक अंतरिक्ष तकनीक और सेवाएं देकर भारत एक तरफ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का वैश्विक दायरा बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) में एक भरोसेमंद तकनीकी भागीदार के रूप में अपनी साख को और मजबूत कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय शिखर बैठक के बाद डॉ. हर्मिनी के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए कहा- हम महासागरों की निगरानी, समुद्री विज्ञान और तटीय प्रबंधन (कोस्टल मैनेजमेंट) के क्षेत्र में भारत के अनुभव और तकनीकी ज्ञान को सेशल्स के साथ साझा करेंगे। उन्होंने आगे कहा, हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे बेहद खुशी है कि आज दोनों पक्षों के बीच इस विषय पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारा मानना है कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम इस दिशा में अपना करीबी सहयोग जारी रखेंगे।

विदेश मंत्रालय ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए खोज और उपयोग में सहयोग का यह

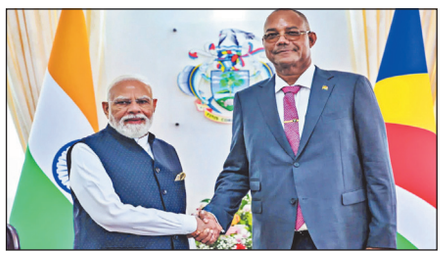

समझौता (एमओयू) भागीदार देशों में भारतीय सैटेलाइट सेवाओं के इस्तेमाल के नए रास्ते खोलेगा। इससे इसरो का वैश्विक दायरा बढ़ेगा और मित्र देशों के लिए एक भरोसेमंद अंतरिक्ष भागीदार के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होगी।

यह समझौता सैटेलाइट सेवाओं, पृथ्वी की निगरानी (अर्थ ऑब्जर्वेशन), मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन, क्षमता निर्माण, ट्रेनिंग और संभवतः सैटेलाइट लॉन्चिंग व ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सहयोग के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करता है। भारत के लिए, इस तरह के समझौते इसरो द्वारा विकसित सैटेलाइट-आधारित सेवाओं को भागीदार देशों में लागू करने का मौका देते हैं।

केवल तकनीक का निर्यात करने के बजाय, भारत उन सेवाओं और क्षमताओं को प्रदान करता है जो विकास से जुड़ी जरूरतों को पूरा करती हैं। इसमें मौसम का पूर्वानुमान, मत्स्य पालन प्रबंधन, कृषि निगरानी, आपदा की चेतावनी देने वाली प्रणाली, समुद्री निगरानी, शहरी नियोजन, टेलीमेडिसिन और दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस एजुकेशन) शामिल हैं। इससे भारत की इमेज स्पेस टेक्नोलॉजी के सिर्फ़ कमर्शियल सप्लायर के बजाय पब्लिक गुड्स के प्रोवाइडर के तौर पर मज़बूत होती है। सेशेल्स एग्रीमेंट एक ऐसे मॉडल को दिखाता है जिसे भारत ने सबसे पहले साउथ एशिया में डेवलप किया था।

इसका सबसे अच्छा उदाहरण GSAT-9 है, जिसे आमतौर पर साउथ एशिया सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, जिसे 2017 में पड़ोसी देशों के फ़ायदे के लिए लॉन्च किया गया था। यह सैटेलाइट भारत ने इस इलाके के देशों को तोहफ़े के तौर पर दिया था और इसने अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका जैसे हिस्सा लेने वाले देशों को कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग सर्विस दी थीं।

इस पहल ने भारत की स्ट्रेटेजिक सोच के कई पहलुओं को दिखाया। भारत ने पड़ोसी देशों के सामने आने वाली डेवलपमेंट से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी देसी स्पेस क्षमताओं का इस्तेमाल किया। जहां चीन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अक्सर लोन और बड़े पैमाने पर फाइनेंसिंग शामिल होती है, वहीं भारत ने ज़्यादातर डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तौर पर सैटेलाइट सर्विस दी। भारतीय सैटेलाइट प्रणालियों का उपयोग करने वाले देश स्वाभाविक रूप से भारत के तकनीकी इकोसिस्टम, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और डेटा-शेयरिंग (डेटा साझा करने की) व्यवस्थाओं से जुड़ जाते हैं। सेशल्स के साथ हुआ यह समझौता भारत के इस दृष्टिकोण को दक्षिण एशिया से आगे बढ़ाकर हिंद महासागर क्षेत्र तक ले जाता है। अंतरिक्ष सहयोग का हर नया समझौता भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को और अधिक मजबूत करता है। इसरो के लिए इस तरह की साझेदारियां कई नए अवसर पैदा करती हैं, जिनमें सैटेलाइट इमेज और डेटा सेवाएं देना, भारतीय रॉकेट्स के जरिए सैटेलाइट लॉन्चिंग सेवाएं प्रदान करना, विदेशी जमीनी स्टेशन और डेटा रिसीविंग केंद्र बनाना शामिल हैं। इसके साथ ही, इससे विदेशी वैज्ञानिकों व इंजीनियरों को ट्रेनिंग देने, संयुक्त अनुसंधान (रिसर्च) प्रोजेक्ट्स पर काम करने और भारत के तेजी से बढ़ते निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए भविष्य के व्यावसायिक अवसर बनाने में मदद मिलती है।

चूंकि भारत वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये साझेदारियां नए बाजार और राजनीतिक सद्भावना तैयार करती हैं। आगे चलकर इसका सीधा फायदा भारतीय लॉन्च प्रदाताओं, सैटेलाइट निर्माताओं और डाउनस्ट्रीम सेवा कंपनियों को मिल सकता है।

पश्चिमी हिंद महासागर में सेशल्स की खास भौगोलिक स्थिति के कारण रविवार को हुए इस समझौते का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। भारत अपनी महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति) जैसी रणनीतिक पहलों के तहत, हिंद महासागर को अपनी सुरक्षा और विदेश नीति रणनीति के केंद्र के रूप में देखता रहा है। अंतरिक्ष सहयोग के जरिए समुद्री क्षेत्र की बेहतर निगरानी, अवैध रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों को पकड़ने, जहाजों के आने-जाने वाले रास्तों पर नजर रखने, खोज और बचाव अभियानों (सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस), और चक्रवात व सुनामी जैसी आपदाओं के समय राहत कार्यों में बड़ी मदद मिल सकती है। इस प्रकार, सैटेलाइट डेटा और इसके उपयोग सीधे तौर पर क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता में अपना योगदान दे सकते हैं।

ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो-पैसिफिक स्टडीज के संस्थापक और अध्यक्ष चिंतामणि महापात्र के अनुसार, रविवार को हुए इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का महत्व इस बात में है कि भारत अंतरिक्ष तकनीक सहित कई क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों को ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) के साथ साझा करने की लगातार कोशिश कर रहा है। महापात्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अब, एक खास क्षमता जिसे पहले केवल दक्षिण एशिया के साथ साझा किया गया था, उसका दायरा बढ़ाकर उसमें अधिक से अधिक ग्लोबल साउथ देशों को शामिल किया जा रहा है, और सेशल्स इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है।

उन्होंने आगे कहा, इसलिए, एक तरह से भारत अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं के आधार पर ग्लोबल साउथ के देशों को हर तरह की सुविधाएं देने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, यह टोह लेने, निगरानी रखने, मौसम का पूर्वानुमान लगाने या किसी भी अन्य काम से जुड़ा हो सकता है। वे सभी फायदे जिन्हें भारत सेशल्स के साथ साझा कर सकता है।

आज का इतिहास

1950 मानसिक रूप से बीमार बौद्ध भिक्षु ने किंकाकू-जी में गोल्डन पैवेलियन में आग लगा दी, जो अब जापान में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है।

1962 पहला वॉलमार्ट स्टोर कारोबार के लिए रोजर, अर्कंसास में खोला गया।

1964 अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन ने सिविल राइट्स एक्टिन्टो कानून (चित्र) पर हस्ताक्षर किए, स्कूलों में कार्यस्थल पर गैरकानूनी अलगाव, और आम जनता की सेवा करने वाली अन्य सुविधाएं।

1976 वियतनाम गणराज्य का पतन; कम्युनिस्ट उत्तर वियतनाम ने अपने संघ को सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ़ वियतनाम बनाने की घोषणा की।

1976 वियतनाम गणराज्य का अंत हुआ। साम्यवादी उत्तरी वियतनाम ने समाजवादी वियतनाम गणराज्य के साथ जुड़ने की घोषणा की।

1976 वियतनाम युद्ध की समाप्ति के एक साल से अधिक समय बाद, उत्तर और दक्षिण वियतनाम आधिकारिक तौर पर साम्यवादी शासन के तहत एकजुट होकर वियतनाम के सोशलिस्ट गणराज्य का गठन किया।

1983 स्वदेश निर्मित परमाणु बिजली केंद्र की पहली इकाई ने मद्रास के निकट कलपक्कम में काम करना शुरू किया।

1990 सऊदी अरब में मक्का-मीना में भगदड़ से 1,426 हज यात्रियों की मौत हो गई।

1997 एशियाई वित्तीय संकट के कारण मार्क थाई थाई ने तेजी से अपना आधा मूल्य खो दिया।

2000 मैक्सिकन आम चुनाव में, विसेंट फॉक्स 71 साल में एक विरोधी पार्टी से मैक्सिको के पहले राष्ट्रपति को दांव पर लगाने के लिए चुना गया था।

2002 अमेरिकी एविएटर स्टीव फॉसेट, बैलून में दुनिया भर में सोलो नॉनस्टॉप उड़ाने वाले पहले व्यक्ति बन गए, जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में उतरने के बाद लगभग 14 दिन की यात्रा पूरी कर रहे थे।

2002 स्टीव फोसेट एक गुब्बारे से दुनिया का लगातार चारों ओर एकल उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने।

2010 कांगो में टैंकर ट्रक विस्फोट में 230 लोगों की मौत हो गई।

2013 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो के चौथे और पांचवें चंद्रमाओं, केर्बेरोस और स्टाइलक्स का नाम दिया।

2015 फिलीपींस में 220 यात्रियों से भरी नौका डूबने से 62 लोगों की मौत हुई।

तुगलकी रास्ते से सत्ता की चाहत का हश्र शिवसेना जैसा होगा

योगेन्द्र योगी

डर और आतंक की राजनीति करने वाली शिवसेना घुटने पर आ चुकी है। नौबत यह आ गई है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार की मोदी सरकार को अपनी शर्तों पर नचाने का सपना देखने वाले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का ठिकाना छिन गया है। खुद सेना के सांसदों ने ही यह कारनामा कर दिखाया है। पार्टी के पूरी तरह से छिन्न भिन्न होने से लाचार उद्धव ने अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकस कर डाली। शिवसेना (यूबीटी) गुट के 6 सांसदों ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थाम लिया।

शिवसेना यूबीटी की संख्या 9 से घटकर 3 रह गई है, जबकि शिंदे गुट की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जिस महाराष्ट्र में एक दौर में एकीकृत शिवसेना की तूती बोलती थी, वहां उसकी बोलती भी लगभग बंद हो जाएगी। इस हालत के लिए शिवसेना खुद जिम्मेदार है। कायदे—कानून भूल कर हर हालत में सिर्फ ताकत के बलबूते सत्ता पाने का ख्वाब देखने वाली शिवसेना यह भूल गई कि संविधान से इतर जाकर गैर लोकतांत्रिक तौर—तरीकों से सत्ता नहीं मिल सकती।

देश के अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की तरह सिकुडती शिवसेना का इतिहास कुछ ज्यादा ही काला रहा है। देश में यदि ममता बनर्जी के बाद किसी ने संविधान और कानून कायदों को ठेंगा दिया है तो वह है शिवसेना। शिवसेना ने भी ममता की तरह अपने ही कायदे कानून चलाने में कसर बाकी नहीं रखी। शिवसेना का ख्याल आते ही, देश के आम जनमानस में महाराष्ट्र में शिवसैनिकों की छवि उभरती थी, हाथों में डंडे या हथियार लिए शिवसैनिक और माथे पर शिवसेना का कपड़ा लपेटे हुए।

शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के दौरान बनी छवि से यह जाहिर होता था कि किसी को कानून की परवाह नहीं है। कानून वही है जो शिवसेना बोल दे। किसी ने जरा भी विरोध करने का दुस्साहस किया तो उसकी खैर नहीं। महाराष्ट्र में चाहे सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो, शिवसेना का आतंक इतना जबरदस्त था कि किसी हिम्मत नहीं थी कि उनकी मनमानी के खिलाफ आवाज उठा सके। बाल ठाकरे ने बाहर से आकर मुंबई बसने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए महाराष्ट्र को सिर्फ मराठियों का कहकर संबोधित किया।

खासतौर पर दक्षिण भारतीय लोगों के विरोध में उन्होंने कई भद्दे नारे भी दिए। शिवसेना का मुखपत्र माने जाने वाले %सामना% समाचार पत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश से मुंबई पलायन करने वाले लोगों को मराठियों के लिए खतरा बता, बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र के लोगों को उनके साथ सहयोग ना करने की सलाह दी। साथ ही इन दो राज्यों से मुंबई बसने वाले नेताओं और अभिनेताओं की भी बाल ठाकरे द्वारा आलोचना की गई।

मोहम्मद अफजल की फांसी की सजा पर कोई फैसला ना सुनाने के लिए बाल ठाकरे ने तत्कालीन राष्ट्रपति ए.पी.जे. अबुल कलाम पर भी अभद्र टिप्पणियां की थी। वैलेंटाइन डे को हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए खतरा बता, दुकानों और होटलों में तोड़-फोड करने के अलावा प्रेमी युगलों पर हमला, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए जनता में बाल ठाकरे के खिलाफ रोष उत्पन्न हो गया।

सचिन तेंदुलकर द्वारा भारत की तेजी से विकसित हो रही वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को सभी भारतीयों का शहर बताने पर बाल ठाकरे भड़क उठे और उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तेंदुलकर मराठी मानसिकता को ठेस पहुंचा रहे हैं। ठाकरे और तेंदुलकर, जो मूल रूप से मराठी थे, के बीच हुई इस तीखी बहस ने राष्ट्रीय स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरीं।

शिवसेना का ताज नहीं मिलने पर अलग हुए भतीजे राज ठाकरे ने भी बाल ठाकरे के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की, किन्तु दाल नहीं गली। संसद सदस्य जया बच्चन भी अपनी कथित मराठी-विरोधी टिप्पणियों के कारण राष्ट्रीय विवाद में फंस गईं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र राज्य और वहां के लोगों का राष्ट्रीय भाषा की आड़ में अपमान करने के लिए जया बच्चन से सार्वजनिक माफी मांगने का आह्वान किया। डर के मारे बच्चन और उनके पति, अभिनेता अमिताभ बच्चन ने सार्वजनिक माफी जारी करते हुए कहा कि वे हिंदी में इसलिए बोले क्योंकि वे उत्तर प्रदेश (उत्तर भारत) से आए थे।

मुंबई या महाराष्ट्र में जिसे रहना है और कारोबार चलाना है, उसे शिवसेना की सारी शर्तों पूरी करनी होती थी। शिवसेना के आगे सिर झुकाने वालों, बॉलीवुड के फिल्मी सितारे, उद्योगपति, क्रिकेटर सहित तमाम दिग्गज हस्तियां शामिल थी। मीडिया भी शिवसेना के बारे में खबर छापने या टीवी पर दिखाने से पहले कई बार सोचता था। यह सब शिवसैनिकों का खौफ था। देश के दूसरे किसी राज्य में ऐसा तांडव किसी राजनीतिक दल का कभी देखने को नहीं मिला, जैसा शिवसेना ने महाराष्ट्र में दिखाया था।

कई दशकों तक शिवसेना की दहशत की यह छाप बनी रही। बाला साहेब के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे और गद्दी नहीं मिलने के कारण शिवसेना छोड़ कर अलग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) बनाने वाले भतीजे राज ठाकरे ने भी इसी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की। सत्ता नहीं मिलने पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने मवालियों वाला तरीका अपनाया और इसको नाम दिया मराठी मानुष और मराठी अस्मिता का।

राजनीति चमकाने के लिए मनसे भाषा और संस्कृति को मुद्दा बना कर गैरकूननी हरकते करने में कसर बाकी नहीं रखी। इसके बावजूद किसी भी तरह के चुनावों में सफलता हासिल नहीं हो सकी। देश के राजनीतिक दलों के लिए शिवसेना और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का हश्र सीखने लायक सबक है। राज्य के विकास के बजाए कानून हाथ में लेकर सत्ता कायम करने की चाहत अंततः क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिए घातक साबित होगी।

भारत-अमेरिका के बीच संबंधों पर बड़े दावे

सुरेंद्र कुमार

फ्रांस के एवियन-लेस-बेंस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की 16 महीने बाद मुलाकात हुई। इस दौरान कई ऐसे घटनाक्रम हुए, जिनकी वजह से भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव और दूरी बढ़ी। इनमें भारत-पाकिस्तान युद्धविराम को लेकर दोनों देशों के अलग-अलग दावे प्रमुख रहे। तनाव तब और बढ़ा, जब अमेरिका ने रूस से तेल आयात पर भारत पर 25 फीसदी दंडात्मक शुल्क लगाया। साथ ही, भारत पर यूक्रेन युद्ध में रूस को वित्तीय मदद देने का आरोप भी लगाया गया, जिसे भारत ने अनुचित बताया था। व्यापार समझौते में अपनी शर्तें मनवाने के लिए अमेरिका का दबाव, भारत से लौट रहे एक ईरानी जहाज को रोके जाने की घटना, भारत को 'नरक' (हेल होल) कहना, 'माउंट सेटे बेलो' जहाज पर हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत, और समुद्री नाकेबंदी के नियमों से जुड़ी भारत की आपत्तियों को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो द्वारा खारिज किया जाना भी विवाद के मुख्य कारणों में रहे। दोनों नेताओं की मुलाकात में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, पर क्या पिछले 16 महीनों में जो कुछ हुआ, वह कोई बुरा सपना था? शायद नहीं! इसीलिए, दोनों नेता अपने-अपने समर्थकों को नाराज किए बिना रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए प्रतिबद्ध थे। 16 जून को आयोजित नेताओं के आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे। ये सुझाव केवल जी-7 देशों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य नेताओं, विशेष रूप से अमेरिका के लिए भी अहम संदेश लेकर आए, जो ट्रंप तक जरूर पहुंचा होगा। यह देश में मोदी की आलोचना करने वालों को भी जवाब था। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि वैश्विक कानूनों का सम्मान न करना वैश्विक एकजुटता और आपसी विश्वास को कमजोर करने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल संकीर्ण राजनीतिक या आर्थिक हितों के लिए हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत व कूटनीति को प्राथमिकता देने की बात दोहराई। साथ ही, 'वैश्विक दक्षिण' को केंद्र में रखकर कई नई पहलों का प्रस्ताव भी रखा। इनका उद्देश्य सम्मानजनक साझेदारी और साझा प्रगति को बढ़ावा देना है। इन्हीं प्रस्तावों में एक है इंपैक्ट (इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन फॉर पार्टनरशिप इन कनेक्टिविटी एंड ट्रेड)। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) की तर्ज पर बनी इस पहल का मकसद बुनियादी ढांचे और व्यापार के निर्माण के लिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीपों में संपर्क बनाना है। दूसरी पहल है ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप। इसका मकसद विकासशील देशों के युवाओं की स्किल मैपिंग व प्रशिक्षण को सरल बनाकर उन्हें वृद्ध होती आबादी वाले विकसित देशों में रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। 'शॉक-एब्जॉर्प्शन सपोर्ट मैकेनिज्म' कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों से बचाने के लिए एक वित्तीय ढांचे का प्रस्ताव देता है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने उनकी खुलकर प्रशंसा की। हालांकि, तारीफों की बारिश से दोनों देशों के बीच मौजूद मतभेद और चुनौतियां खत्म नहीं हो जातीं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि ट्रंप का जी-2 आइडिया कैसे आगे बढ़ता है। अमेरिकी सैन्य कमान के लिए पुराने नाम 'एशियन पैसिफिक कमांड' को फिर से अपनाने के संकेत इशारा करते हैं कि भारत का महत्व कम हो रहा है और चीन-विरोधी बयानबाजी धीमी पड़ रही है। इसका असर क्वाड पर भी पड़ने की पूरी संभावना है।

बंगाल में राजनीतिक प्रतिमान परिवर्तन

देवेन्द्र कुमार बुडाकोटी

मई 2026 में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आना राज्य की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। कभी बंगाल की राजनीति में प्रभावशाली शक्ति रहे वामपंथी दल आज भी अस्तित्व में हैं, किंतु उनका प्रभाव सीमित हो चुका है। वहीं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भी बड़े पैमाने पर राजनीतिक परिदृश्य से हाशिए पर चली गई है। अधिकांश लोगों ने इसकी राजनीतिक पराजय और भाजपा के सत्ता में आने के बाद होने वाले सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों की कल्पना नहीं की थी। राजनीतिक विश्लेषक भी इस परिवर्तन का पूर्वानुमान नहीं लगा सके, जबकि बंगाल को कला, विज्ञान, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बुद्धिजीवियों—'भद्रलोक'—की भूमि माना जाता रहा है।

गोपाल कृष्ण गोखले का प्रसिद्ध कथन, आज बंगाल जो सोचता है, भारत कल वही सोचता है, उस दौर में सामने आया था जब बंगाल ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत के बौद्धिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक जागरण का केंद्र था। यह समझने के लिए कि क्या यह विचार आज भी प्रासंगिक है, बंगाल की राजनीतिक और बौद्धिक संस्कृति के ऐतिहासिक विकास तथा समकालीन राजनीति में भद्रलोक वर्ग की बदलती भूमिका का अध्ययन आवश्यक है।

ब्रिटिश शासन के दौरान कलकत्ता (वर्तमान कोलकाता) ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश भारत की राजधानी (1911 तक) था। यहीं से औपनिवेशिक प्रशासन भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से का संचालन करता था। उन्नीसवीं शताब्दी में प्रशासनिक संस्थाओं के विस्तार के साथ बंगाल भारत के उन प्रथम क्षेत्रों में शामिल हुआ जहाँ कानून, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, साहित्य और राजनीतिक चिंतन जैसे क्षेत्रों में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ।

उन्नीसवीं शताब्दी में ही बंगाल पुनर्जागरण का उदय हुआ, जो राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रवीन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद जैसी महान विभूतियों से जुड़ा था। इन समाज सुधारकों ने सती प्रथा जैसी कुरीतियों को चुनौती दी, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, तर्कशील चिंतन को प्रोत्साहित किया और आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

परिणामस्वरूप बंगाल औपनिवेशिक भारत में बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया।

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में बंगाल औपनिवेशिक-विरोधी राजनीति, श्रमिक आंदोलनों और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का भी प्रमुख आधार बना। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग तीन दशकों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की राजनीति पर प्रभुत्व बनाए रखा। किंतु सामाजिक असंतोष, श्रमिक संघर्षों, किसान आंदोलनों और कांग्रेस शासन के प्रति बढ़ती निराशा ने धीरे-धीरे वामपंथी राजनीति को मजबूत किया।

1977 में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा (ख्द्धद्ब स्नह्श्ठ्ठ्ल) सत्ता में आया और लगातार 34 वर्षों तक शासन करता रहा। इस अवधि में पश्चिम बंगाल भारत में वामपंथी विचारधारा का सबसे सशक्त केंद्र बन गया। ट्रेड यूनियन, किसान संगठन और बौद्धिक वर्ग व्यापक रूप से मार्क्सवादी राजनीति से प्रभावित थे। अनेक पर्यवेक्षकों को लगता था कि बंगाल में वामपंथी प्रभुत्व स्थायी है। किंतु लंबे शासन के बाद वामपंथ का पतन राजनीतिक विश्लेषकों और समाज वैज्ञानिकों दोनों के लिए आश्चर्य का विषय बना।

2011 में ममता बनर्जी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का उदय एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन था। टीएमसी ने कांग्रेस और वाम दलों दोनों से नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ा तथा स्वयं को बंगाली अस्मिता और लोककल्याणकारी राजनीति पर आधारित क्षेत्रीय विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया।

2014 के बाद एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बंगाल में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। परंपरागत रूप से राज्य में कमजोर मानी जाने वाली भाजपा ने शहरी मध्यवर्ग, हिंदू मतदाताओं, अनुसूचित जातियों, आदिवासी समुदायों तथा टीएमसी और वामपंथ से निराश युवा मतदाताओं के बीच तेजी से अपना आधार बढ़ाया।

राष्ट्रवाद, नागरिकता, सीमा सुरक्षा, धार्मिक पहचान तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) जैसे मुद्दे सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में आ गए। भाजपा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जैसी ऐतिहासिक विभूतियों को केंद्र में रखकर बंगाल की सांस्कृतिक विरासत की नई व्याख्या करने का प्रयास किया। इससे पुराने भद्रलोक वर्ग से जुड़ी वाम-उदारवादी बौद्धिक परंपराओं को चुनौती मिली।

हालाँकि, बंगाल का राजनीतिक इतिहास केवल अभिजात बुद्धिजीवियों तक सीमित नहीं रहा है। नील विद्रोह, तेभागा आंदोलन, किसान संघर्ष, श्रमिक आंदोलनों और नक्सलबाड़ी विद्रोह जैसे जनआंदोलनों ने सिद्ध किया कि बंगाल की राजनीति आम जनता की व्यापक भागीदारी से भी निर्मित हुई है।

क्या बंगाल आज भी भारत का वैचारिक और राजनीतिक मार्गदर्शक है, जैसा कि गोखले के प्रसिद्ध कथन से संकेत मिलता है, यह बहस का विषय हो सकता है। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि बंगाल आज भी भारत के सबसे राजनीतिक रूप से सक्रिय, वैचारिक रूप से संघर्षशील और सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली क्षेत्रों में से एक है।

मई 2026 में भाजपा के बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद यह प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या पश्चिम बंगाल वास्तव में एक नए राजनीतिक प्रतिमान परिवर्तन (क्ठ्ठह्ड्डस्त्रद्बद्द स्द्धद्बद्धह्ल) के दौर से गुजर रहा है। पुनर्जागरण और वामपंथी राजनीति के केंद्र से राष्ट्रवाद, क्षेत्रीय पहचान और जमीनी लोकतंत्र के नए विमर्शों तक बंगाल की यह यात्रा भारत में हो रहे व्यापक सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों का प्रतिबिंब प्रतीत होती है।

ऐसी स्थिति में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या बंगाल आज भी भारत की राजनीति और समाज की भावी दिशा की एक प्रारंभिक झलक प्रस्तुत कर रहा है?

स्मृति ईरानी को केंद्र में लौटने की उम्मीद?

हरीश गुप्ता

राजनीति भी टेलीविजन की तरह वापसी की कहानियों को पसंद करती है। और इसे स्मृति ईरानी बेहतर शायद ही कोई समझता हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार के बाद स्मृति ईरानी लगभग राजनीतिक सुर्खियों से गायब हो गई थीं। कभी भाजपा का सबसे मुखर और प्रभावशाली चेहरा मानी जाने वाली ईरानी लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर नजर आईं।

इस दौरान उन्होंने फिर से टेलीविजन अभिनय का रुख किया, जबकि दिल्ली में संगठन से जुड़ी जिम्मेदारियां भी चुपचाप निभाती रहीं। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया, जब महिलाओं के आरक्षण के जल्द लागू होने से जुड़े विधेयकों को लेकर संसद में मोदी सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अचानक भाजपा को इस मुद्दे पर एक भरोसेमंद और प्रभावी वक्ता की जरूरत महसूस हुई।

पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री रह चुकी स्मृति ईरानी इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त रहीं। देखते ही देखते टीवी चैनलों ने उन्हें फिर से प्रमुखता देनी शुरू कर दिया। सरकार को संसद में झटका लगने के अगले ही दिन भाजपा ने उन्हें एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी का पक्ष रखने की जिम्मेदारी सौंपी। यहीं से उनकी वापसी का सिलसिला और मजबूत हो गया।

बंगाली भाषा पर अच्छी पकड़ और लोगों को आकर्षित करने की क्षमता के कारण स्मृति ईरानी को पश्चिम बंगाल में पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में भेजा गया। उनकी दोबारा प्रमुख भूमिका में वापसी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि हाल के दिनों में भाजपा के नए पसंदीदा चेहरे, जैसे रेखा गुप्ता और कंगना रणावत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे थे। फिलहाल ऐसा लगता है कि स्मृति ईरानी राजनीतिक हाशिये से निकलकर फिर से अहम भूमिका निभाने की स्थिति में आ गई हैं। वह अभी मुख्य भूमिका में नहीं हैं, लेकिन फिर से सक्रिय और दिखाई देने लगी हैं।

समाजवादी पार्टी का गढ़ क्यों नहीं भेद पा रही भाजपा

पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जल्द ही बड़ी टूट होने वाली है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं भाजपा के सहयोगी ओमप्रकाश राजभर ने तो अखिलेश यादव को अपने सांसदों को बचाने की चुनौती तक दे डाली।

लेकिन जिस बगावत की इतनी चर्चा हो रही है, वह अब तक सामने नहीं आई है। कागज पर देखें तो सपा कमजोर नजर आती है। लोकसभा में उसके 37 सांसद हैं और राज्यसभा में केवल चार सदस्य। उसके कई सांसद गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। अगर इनमें से किसी को दो साल से ज्यादा की सजा हो जाती है, तो उसकी संसद सदस्यता भी जा सकती है।

दूसरी पार्टियों में ऐसी परिस्थितियां अब तक टूट का कारण बन चुकी होतीं। फिर ऐसा क्या है कि भाजपा समाजवादी पार्टी में टूट नहीं करा पा रही है? इसका जवाब कानूनी मजबूरियों से ज्यादा राजनीतिक गणित में छिपा है। दूसरे कई क्षेत्रीय दलों के विपरीत समाजवादी पार्टी आज भी उत्तर प्रदेश में भाजपा की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी पार्टी मानी जाती है।

उसके सांसद मजबूत भाजपा विरोधी जनादेश के दम पर जीतकर आए हैं और वे जानते हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य काफी हद तक अखिलेश यादव की राजनीतिक ताकत से जुड़ा है। पार्टी छोड़ने से उन्हें कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है, लेकिन उन क्षेत्रों में उनकी राजनीतिक पहचान कमजोर पड़ सकती है, जहां मतदाता अब भी समाजवादी पार्टी को भाजपा की मुख्य चुनौती मानते हैं।

प्रधान के मामले में भाजपा का साफ संदेश

संकेत हैं कि आने वाला मानसून सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना मुख्य निशाना बना लिया है। अगर विपक्ष परीक्षा से जुड़े विवादों को लेकर उन्हें घेरने की तैयारी कर रहा है, तो भाजपा ने भी साफ कर दिया है कि वह उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाएगी। राजनीतिक संदेश बिल्कुल स्पष्ट है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज होने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। भाजपा में इसे नेतृत्व के भरोसे और इस संकेत के रूप में देखा गया कि पार्टी पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। विपक्षी दल, छात्र संगठन और कई सामाजिक कार्यकर्ता नीट-यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों, पेपर लीक और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के कामकाज को लेकर सरकार पर हमले तेज कर रहे हैं। विपक्ष इसे लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों की चिंताओं के प्रति सरकार की कथित असंवेदनशीलता दिखाने का बड़ा मुद्दा मान रहा है।

दूसरी ओर भाजपा पीछे हटने के किसी मूड में नहीं दिख रही है। ऐसे में मानसून सत्र के दौरान एक सीधी राजनीतिक टक्कर तय नजर आ रही है। एक ओर जवाबदेही की मांग करता आक्रामक विपक्ष होगा, तो दूसरी ओर किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं दिख रही सरकार।

स्वदेशी आसमानी निगरानी क्षमता से आत्मनिर्भरता की ओर

रवींद्र दुबे

हाल ही में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारतीय वायुसेना को स्वदेशी नेत्र एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (एईडब्ल्यू एंड सी) प्रणाली का फाइनल ऑपरेशनल क्लीयरेंस (एफओसी) सौंप दिया। यह भारत के सबसे लंबे और कठिनतम एयरोस्पेस कार्यक्रमों में से एक की अंतिम परिणति है। नेत्र प्रणाली ने सभी विकासात्मक, उपयोगी और परिचालन संबंधी परीक्षण पूरे कर लिए हैं और अब वह युद्धक अभियानों के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, आधुनिक हवाई युद्ध अब सबसे तेज लड़ाकू विमान रखने भर की बात नहीं रही। जीत इस पर निर्भर करती है कि दुश्मन को पहले कौन देखता है। एईडब्ल्यू एंड सी विमान असल में एक उड़ता हुआ रडार स्टेशन है। यह युद्धक्षेत्र के ऊपर ऊंचाई पर मंडराते हुए विशाल हवाई क्षेत्र को स्कैन करता है, दुश्मन के विमानों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों को जमीनी रडार से तेजी से पकड़ सकता है और यह जानकारी तुरंत लड़ाकू विमानों तथा कमान केंद्रों तक पहुंचा देता है। इसके विपरीत, किसी पहाड़ या जमीनी स्टेशन पर लगा रडार पृथ्वी की वक्रता से बंधा होता है, जबकि तीस हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ता यह विमान रडार की पहुंच को कई सौ किलोमीटर आगे बढ़ा देता है। निगरानी के अलावा, यह विमान कई लड़ाकू दस्तों के बीच तालमेल बिठाने, लक्ष्यों को प्राथमिकता देने, अंतर्रोधी मिशनों का मार्गदर्शन करने और जटिल अभियानों के दौरान एक उड़ता हुआ कमान केंद्र बनने जैसे युद्ध-प्रबंधन का काम भी करता है। 1999 के कारगिल संघर्ष ने भारत की निगरानी क्षमता की सीमाओं को उजागर किया था। इस लड़ाई के दौरान सैन्य रणनीतिकारों को अच्छी तरह समझ में आ गया था कि तकनीकी रूप से सक्षम दुश्मन के साथ आगामी लड़ाइयों में निरंतर हवाई निगरानी और एकीकृत कमान नियंत्रण बहुत जरूरी है। भारत को अपना स्वदेशी हल चाहिए था। यह रडार एक साथ कई हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक कर सकता है। साथ ही, मित्र और शत्रु विमानों में फर्क भी कर सकता है। उन्नत ऑनबोर्ड कंप्यूटर कई सेंसरों से मिली जानकारी को मिलाकर मिशन ऑपरेटरों के सामने एक संपूर्ण सामरिक तस्वीर पेश करते हैं। यह तस्वीर फिर सुरक्षित रूप से जमीनी स्टेशनों और लड़ाकू विमानों तक भेजी जाती है। इससे सैन्य अभियानों के दौरान स्थितिजन्य जागरूकता काफी बेहतर हो जाती है। अंतिम परिचालन मंजूरी (एफओसी) मिलने से पूर्व ही भारतीय वायुसेना कई वर्षों से तीन नेत्र विमानों को उड़ा रही थी। रक्षा अधिकारियों के अनुसार, 2019 के बालाकोट अभियान के दौरान नेत्र विमानों ने हवाई निगरानी बनाए रखने और कमान-नियंत्रण कार्यों में सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रक्षा अधिग्रहण में एफओसी महज एक रस्मी पड़ाव नहीं है, बल्कि यह प्रमाणित करता है कि प्लेटफॉर्म ने विकासात्मक परीक्षण, उपयोगकर्ता मूल्यांकन, भरोसेमंद जांच और परिचालन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और यह वास्तविक परिचालन परिस्थितियों में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। वायुसेना के लिए इसका मतलब है कि अब नेत्र को बेझिझक कहीं भी तैनात कर युद्धकालीन योजना में पूरी तरह शामिल किया जा सकता है। यह उन स्वदेशी तकनीकों की परिपक्वता पर भरोसे को भी दर्शाता है, जिन पर मुट्ठी भर देशों ने ही महारत हासिल की है। यह गर्व की बात है कि अब भारत भी उनमें से एक है। हालांकि, कई तकनीकी विवरण अब भी गोपनीय हैं, लेकिन यह निर्विवाद है कि नेत्र कई सौ किलोमीटर के दायरे में एक साथ कई हवाई लक्ष्यों का पता लगाकर उन्हें ट्रैक कर सकता है। यह निगरानी, पहचान, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और युद्ध-प्रबंधन के साथ मिलकर काम करता है। इस पर सवार मिशन ऑपरेटर लड़ाकू विमानों के साथ तालमेल बिठा सकते हैं, दुश्मन की हवाई गतिविधि पर नजर रख सकते हैं, लक्ष्य तय कर सकते हैं और कमांडरों को वास्तविक समय में सामरिक जानकारी भेज सकते हैं। जमीनी रडार के विपरीत यह आसमानी प्लेटफॉर्म उन कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को भी पकड़ सकता है, जो जमीनी आकृतियों के पीछे छिपकर पकड़ में आने से बचने की कोशिश करते हैं। इसकी गतिशीलता इसे अलग-अलग जरूरतों के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में तेजी से तैनात करने की सुविधा भी देती है। नेत्र मार्क-1 का प्रमाणीकरण एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने नेत्र मार्क-2 के विकास को मंजूरी दे दी है, जो एयरबस ए-321 विमान पर आधारित एक बड़ा एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (एवैक्स) होगा। इससे लगभग 360 डिग्री रडार कवरेज मिलने की उम्मीद है, जबकि मौजूदा नेत्र सीमित दिशाओं में ही कवरेज देता है। ऐसे छह विमानों के विकास को मंजूरी दी गई है, जिससे भारत की आसमानी निगरानी क्षमता काफी मजबूत होगी।

सलाह

पार्टनर से कर रहे हैं चैट तो रखें खास बातों का ख्याल

आजकल के मॉडर्न जमाने में मोबाइल हर किसी की जरूरत बन गया है। सुबह हो या रात इसको देखे बिना आजकल के युवाओं का मन ही नहीं लगता। यहां तक की पार्टनर भी आपस में बात करने के लिए ज्यादातर चैटिंग का ही सहारा लेते हैं। कई बार तो चैटिंग से बात स्पष्ट न होने के कारण छोटी सी बात भी बड़े झगड़े का कारण बन जाती है। आप भी पार्टनर के साथ बात करने के लिए चैटिंग का सहारा ले रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें।

1. टाइम का रखें ख्याल

यह जरूरी नहीं की आपका पार्टनर हर समय चैटिंग करने के लिए फ्री हो। बिजनेस के कारण या किसी जरूरी मीटिंग के वक्त उनको डिसटर्ब न करें। बात करने के लिए सही मौके का इंतजार करें।

2. विषय से न भटके

इस बात का ख्याल रखें कि चैटिंग एक-दूसरे का हाल पूछने या फिर जरूरी बात के लिए अच्छा विकल्प है। बात करते समय विषय से न भटके

3. न करें छोटी-छोटी बात

छोटी-छोटी बात के लिए चैटिंग करने से आपके पार्टनर को बुरा भी लग सकता है। जो बात जरूरी है सिर्फ वहीं करें।

4. सहजता से करें चैटिंग

चैटिंग करते समय इस बात का ख्याल रखें कि हड़बडाहट या घबराहट में बात न करें। इससे आपको अपनी बात दूसरे को समझाने में परेशानी हो सकती है।

ज्यादा अपेक्षाएं मत पालो, आरामदायक जीवन का मंत्र

एक बार भ्रमण पर निकले दार्शनिक सुकरात की मुलाकात किसी शहर में एक बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग सुकरात को अपने घर ले गए। उनका भरा-पूरा परिवार था। घर में बेटे-बहुओं के अलावा पौत्र-पौत्रियां भी थे। सुकरात ने पूछा-आपके घर में तो सुख-समृद्धि का वास लग रहा है। वैसे अब आप करते क्या हैं? बुजुर्ग ने कहा-अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। ईश्वर की कृपा से हमारा अच्छा कारोबार है, सारी जिम्मेदारियां अब मैंने अपने बेटों को सौंप दी हैं। घर का जिम्मा बहुएं संभालती हैं। इसी तरह जीवन चल रहा है। सुकरात ने फिर पूछा-पर आपको कुछ तो करना ही पड़ता होगा। बुढ़ापे में आपके इस सुखी जीवन का रहस्य क्या है? सुकरात की बात सुनकर बुजुर्ग बोला-मैंने जीवन के इस मोड़ पर बस एक ही फलसफा अपनाया है कि दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएं मत पालो। जो मिले, उसमें संतुष्ट रहो। मैं और मेरी पत्नी अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने बेटे-बहुओं को सौंपकर निश्चिंत हैं। अब वे जो कहते हैं, वह मैं कर देता हूं और जो कुछ भी खिलाते हैं, वह खा लेता हूं। अपने पौत्र-पौत्रियों के साथ हंसता-खेलता हूं। बच्चे जब कुछ भूल करते हैं, तब भी मैं चुप ही रहता हूं। जब कभी वे मेरे पास सलाह-मशविरे के लिए आते हैं, तो मैं अपने जीवन के सारे अनुभवों को उनके सामने रखते हुए उनके द्वारा की गई भूल से उत्पन्न दुष्परिणामों के प्रति उन्हें सचेत कर देता हूं। मेरी सलाह पर वे कितना अमल करते हैं, यह देखना मेरा काम नहीं है। यदि वे मेरे पास पुन: आते हैं, तो मैं नेक सलाह देकर उन्हें विदा कर देता हूं। यह सुनकर सुकरात बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा-इस आयु में जीवन कैसे जिया जाए, यह आपने बखूबी समझ लिया है।

क्या आप जानते हैं इन हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में

कभी हेयर स्टाइल का मतलब हुआ करता था बॉलीवुड के स्टार्स की तरह की स्टाइल। किसी खास फिल्म में अपने पसंदीदा कलाकार की हेयर स्टाइल की कॉपी करने तक ही हेयर स्टाइलिंग का मामला सिमटा हुआ था। इससे ज्यादा हेयर स्टाइल का कोई मतलब भी नहीं था। बीते कुछ सालों में बालों ने स्टाइलिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर लिया है। इसके साथ ही शुरू हुई है हेयर स्टाइलिंग और केयरिंग प्रॉडक्ट्स की मांग।

ये हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स भी बाजार में बड़ी रेंज उपलब्ध होते हैं। जानते हैं ऐसे ही कुछ प्रॉडक्ट्स के बारे में।

वैक्स

इसे मोल्डिंग क्रीम, स्टाइलिंग पेस्ट, क्ले या पुट्टी के तौर पर भी जाना जाता है। यह हेयर स्टाइलिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला बहुत आम प्रोडक्ट है। इसका हर दिन उपयोग किया जा सकता है। आपके बाल चाहे स्ट्रेट हों या वेवी, ज्यादा लंबे हों या फिर छोटे... हर तरह के बालों में आप वैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको बालों को होल्ड करके रखता है और साथ ही हल्की-सी चमक भी देता है।

पॉमेड

यदि आप बालों को और भी ज्यादा व्यवस्थित व चमकदार चाहते हैं, तो पॉमेड सबसे उपयुक्त उत्पाद है। अपने बालों को वेल-ग्रूम्ड और एकदम संवरे हुए रखने के लिए टॉवेल से बालों को सुखाकर पॉमेड का इस्तेमाल करें। एक बार सूखने पर आपके बाल संवरे और चमकदार नजर आएंगे। चूंकि यह आपको बालों को हल्का-सा चिपचिपा बनाता है, इसलिए उन लोगों के लिए यह बहुत अच्छा विकल्प नहीं है, जो अपने बालों को अपने हाथों से संवारते हैं।

क्रीम

हेयर क्रीम बालों को पूरी तरह से संवरा हुआ नहीं रखता है, लेकिन इससे लंबे और कर्ली बाल बहुत अच्छे तरीके से संभाले जा सकते हैं। हेयर क्रीम बालों को अच्छे-से नम रखता है ताकि वे सही दिशा में संवरे रहें।

ड्राय शैंपू

हर दिन बालों में शैंपू करना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इससे बालों से प्राकृतिक नमी कम होने लगती है और यह बालों की सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। यदि आप शैंपू नहीं करते हैं, तब भी आपके बाल चिपचिपे हो जाते हैं। इससे निबटने और बालों को नुकसान से बचाने के लिए आप ड्राय शैंपू का उपयोग करें। इसे आप सूखे बालों पर स्प्रे करें ताकि यह आपके बालों में से चिपचिपापन सोख ले। इससे आपके बाल एकदम फ्रैश नजर आने लगेंगे। साफ बाल ज्यादा घने भी नजर आते हैं।

जेल

जेल सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय उत्पाद है। एक अच्छा हेयर जेल हर दिन प्रयोग करने के लिए अच्छा विकल्प है। इससे आपकी स्टाइलिंग एकदम परफेक्ट रहेगी। जरा-सा जेल टॉवेल से सुखाए गए बालों पर लगाएं।

स्मार्टफोन डाटा और पैसे बचाने के लिए उपयोग करें ये 5 तरीके

प्रीपेड मोबाइल यूजर्स के साथ बैलेंस को लेकर कई समस्याएं आती हैं। जैसे यूजर्स को डाटा बैलेंस खत्म होने का पता नहीं चलता है जिसके चलते मेन बैलेंस से डाटा इस्तेमाल हो रहता है। ऐसे में यूजर का सारा बैलेंस खत्म हो जाता है। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। इसी परेशानी को देखते हुए हम आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लाएं हैं जो आपका डाटा बचाने में मदद करेंगे। इससे आपका बैलेंस भी जीरो नहीं होगा।

ऐसे बचाएं मोबाइल डाटा व पैसा

» देखा जाए तो एप्स अपडेट होने में ज्यादा डाटा खर्च होता है। जैसे ही फोन में इंटरनेट कनेक्ट होता है वैसे ही एप्स अपडेट होने लगती है। ऐसे में अगर आप एप्स का ऑटो अपडेट ऑप्शन बंद कर दें या उसे ओनली वाई-फाई पर सेट कर दें तो आपका डाटा बच सकता है।

» व्हाट्सएप इस्तेमाल करते समय यह ऐप काफी डाटा खर्च करती है। दरअसल, व्हाट्सएप पर आने वाली इमेज और मीडिया फाइल्स अपने आप ही डाउनलोड हो जाती हैं। इससे यूजर्स का मोबाइल डाटा काफी खर्च होता है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप सेटिंग्स में जाकर यूसेज पर क्लिक करना होगा। इशके बाद यहां आपको मीडिया ऑटो डाउनलोड के ऑप्शन मिलेंगे जिन्हें आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। आप इन्हें ऑटो डाउनलोड ओवर वाई-फाई पर सेट कर सकते हैं।

» अगर आप अपने स्मार्टफोन पर क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो यह इससे आपका मोबाइल डाटा ज्यादा खर्च होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रोम किसी भी वेबसाइट के वेब वर्जन डाउनलोड करता है। ऐसे में आप किसी भी साइट का लाइट वर्जन ब्राउज करें। इसके लिए क्रोम सेटिंग्स पर जाकर डाटा सेवर ऑप्शन को ऑन कर दें।

» फेसबुक चलाते समय उसके वीडियोज भी ऑटो प्ले होते हं। इससे फोन का डाटा ज्यादा खर्च होता है। इसके लिए फेसबुक एप की सेटिंग में जाकर ऑटोप्ल को ऑफ कर दें।

» आपके फोन में गूगल ड्राइव, कैंडी क्रश, जीमेल जैसे कई एप्स मौजूद होंगे। ये सभी एप्स मोबइल डाटा ऑन होते ही फाइल्स को ऑनलाइन सेव/सिंक करते हैं। इससे डाटा काफी खर्च होता है। इसक लिए आप नोटिफिकेशन टॉगल में जाकर sync ऑफ कर दें।

कुछ इस तरह सुंदर पौधे लाएंगे घर में खुशहाली

फेंगशुई के अनुसार स्वस्थ और सुंदर पौधे आपके घर में खुशियां लाते हैं और घर के हर कोने को उत्साह और उमंग से सराबोर कर देते हैं।

फेंगशुई में पौधों को नौ आधारभूत सुरक्षा सावधानियों में से एक माना गया है, इसलिए घर के खाली हिस्सों में पौधे लगा देना चाहिए।

» चढ़ने वाली बेलें जिन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है जैसे- मनी प्लांट को कोने में लगाकर उस जगह की उदासीनता को कम किया जा सकता है।

» घर के दक्षिण-पूर्व कोने को धन और समृद्धि का कोना माना जाता है इसलिए यहां चौड़े पत्तियों वाले पौधे लगाना चाहिए।

» मुरझाए हुए या सूख गए पौधों को तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है।

» घर के सामने वाले हिस्से में कांटेदार या नुकीले पत्तों वाले पौधे नहीं लगाना चाहिए। वे नकारात्मक ऊर्जा को सहयोग करते हैं।

» ये पौधे न सिर्फ आपके घर को बल्कि आपके जीवन को भी महकाते हैं और सबसे बड़ी बात कि इन्हें फॉलो करना बहुत कठिन भी नहीं है।

सलाह

करी पत्ते से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में जानते हैं आप?

करी पत्ते को मीठी नीम भी कहा जाता है। अक्सर खाने का जायका बढ़ाने के लिए घरों में करी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। हमें दक्षिण भारत के व्यंजनों में ज्यादातर करी पत्ते का इस्तेमाल देखने को मिलता है। करी पत्ता ना केवल खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाता है बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। करी पत्ते में मौजूद पोषक तत्व शरीर को कई बीमारियों से दूर रखते हैं। करी पत्ते में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। करी पत्ते में विटामिन ए-सी-बी-ई, आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड की भरपूर मात्रा होती है। करी पत्ता बालों और त्वचा दोनों के लिए अच्छा माना जाता है।

करी पत्ते के ये फायदे जानकर हैरान हो जाएंगे आप

वजन घटाने में मददगार: अगर बढ़े हुए वजन से परेशान हैं तो अपने मेन्यू में करी पत्ते को शामिल करें। रोजाना करी पत्ते के सेवन से शरीर की जमी हुई चर्बी घटेगी और वजन आसानी से कम होगा।

लीवर दुरुस्त रखे : करी पत्ते में मौजूद विटामिन-ए और सी लीवर को तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं। अधिक मात्रा में स्मोकिंग करने या शराब पीने से लीवर कमजोर हो जाता है। ऐसे में करी पत्ता खाना फायदेमंद साबित हो सकता है।

दिल को रखे स्वस्थ : करी पत्ते के सेवन से आप दिल से जुड़ी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। बता दें, करी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट गुण शामिल होते हैं जो शरीर में खराब कोलेस्ट्रोल को बढ़ने से रोकते हैं।

एनीमिया से बचाए : करी पत्ता आयरन और फॉलिक एसिड का अच्छा स्रोत है, जो एनीमिया के खतरे को कम करने में सहायक है।

डायबिटीज के लिए असरदार : करी पत्ते में एंटी डायबिटिक एजेंट होते हैं। इसके लगातार सेवन से शुगर लेवल को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। करी पत्ता इन्सुलिन को प्रभावित कर ब्लड-शुगर लेवल को कम करता है।

त्वचा, बालों के लिए फायदेमंद : करी पत्ता त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। दाग-धब्बों और मुंहासों से निजात पाने के लिए करी पत्ते का इस्तेमाल करें। करी पत्ते का फेस पैक लगाने से आप चेहरे की रंगत निखार सकते हैं।

अगर काले, लंबे और घने बालों का शौक रखती हैं तो करी पत्ते का इस्तेमाल करें। करी पत्ता बालों का झड़ना, रुसी और रुखापन कम करता है। करी पत्ते को उबालने के बाद हरे रंग के पानी से बालों की अच्छे से मालिश करें।

आंखों की रोशनी बरकरार रखे : करी पत्ते में भरपूर मात्रा में विटामिन-ए होता है, जो आंखों के लिए फायदेमंद होता है। करी पत्ते के लगातार सेवन से आंखों से जुड़ी बीमारियों से निजात मिल सकती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है।

इंफेक्शन से बचाए : करी पत्ते में मौजूद एंटी ऑक्सिडेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण त्वचा के लिए गुणकारी हैं। त्वचा में इंफेक्शन होने पर करी पत्ते का इस्तेमाल असरदार साबित होता है।

पाचन क्रिया स्वस्थ रखे : करी पत्ता पाचन संबंधी परेशानियों से छुटकारा दिलाने का बेहतरीन उपाय है। करी पत्ता कब्ज, अपच, बवासीर और डायरिया जैसी परेशानियों से आपको बचाता है।

बुलंदियों तक पहुँचायेगी अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी

समय के साथ क्वालिटी लीडरशिप की डिमांड बढ़ती जा रही है। आप बिजनेस, टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी फील्ड के लिए काम कर रहे हो, खुद में लीडरशिप स्किल को लाने की कोशिश करे। क्या पता आपकी यह खासियत आपको बुलंदी पर पहुंच दे। कुछ टिप्स को अपनाकर आप अच्छी लीडरशिप डेवलप कर सकते है।

लोगों को करे प्रभवित : अपनी बुद्धिमत्ता और तार्किकता के बल पर कंपनी को फायदा पहुंचना एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। आप अपने कार्य और व्यवहार से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करे। एक्सपर्ट मानते है की लीडरशिप एक आर्ट है और इसे भी निखारा जा सकता है। सभी लोग जन्मजात स्टार नहीं होते, लेकिन लीडरशिप टूल्स का उपयोग कर अपने टैलेंट को निखारते रहते है और लोगो के लिए रोल मॉडल बन जाते है।

सीखने के लिए तैयार रहे: एक अच्छा लीडर हमेशा सीखने को तैयार रहता है। यहीं कारण है कि वह हमेशा खुद को अप टू डेट रखता है। एक स्मार्ट लीडर वर्तमान से संतुष्ट रहते हुए भी नई चीजों के लिए तैयार रहता है। वह अपनी टीम को भी यही सीख देता है।

टीम का हौसला बढ़ायें : एक अच्छा टीम लीडर हमेशा अपनी टीम का सपोर्ट करता है और टीम मेंबर्स का हौसला बढ़ाता है। विपरीत परिस्थिति में टीम से खुलकर बात करता है और खुलकर बात करने का मौका भी देता है। एक्सपर्ट की माने तो लीडरशिप का सही मतलब असर डालना, दिशा दिखाना और हमेशा सपोर्ट करना है, न कि चीजों को कंट्रोल करना।

पारदर्शिता रखें : अच्छे लीडर को कार्य एवं व्यहार में पारदर्शिता दिखने कि जरूरत होती है। अपने काम के प्रति लीडर को हमेशा ईमानदारी और लगन दिखाने की जरूरत होती है। इससे वह टीम का भरोसा एवं दुसरो के लिए मानक भी स्थापित कर पता है।

जूनियर्स को सम्मान दे: जब कंपनी आपको लीडरशिप का मौका देती है, तो वह चाहती की आप उसके लिए हर तरीके से बेहतर साबित हो। इसलिए अपने जूनियर्स को सम्मान दे और आप खुद अहंकार को न बढ़ने दे।

सहयोग के लिए तैयार रहे : वर्क पैलेस पर आपकी जिम्मेदारी और जबाबदेही बनती है की आप सहयोग की भावना से काम करें। इसके साथ ही आपको स्ट्रांग लीडरशिप की कला से खुद को सजाना ही होगा।

व्यवसाय को इस प्रकार बनाये लाभकारी

कारोबार बढ़ाने में भी वास्तु के उपाय बेहद लाभदायक होते हैं। कार्यालय वह जगह है जहां लोग पेशेवर ढंग से अपने पेशे और व्यापार के लिए लक्षित होकर काम करते हैं। यह जगह धन सृजन के साथ-साथ प्रतिष्ठा और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की जगह है। सैद्धांतिक तौर पर ऑफिस को सकारात्मक उर्जा से भरा होना चाहिए, माहौल में रौशनी की अधिकता होनी चाहिए, साथ इसका डिजायन भी आकर्षक और सुविधाजनक होना चाहिए। भारतीय वास्तुशास्त्रों में ऑफिस को व्यवसाय स्थल, कार्यस्थान या कार्यालय कहा गया है और अनेक विस्तृत उपायों की चर्चा की गई, जिसे अपना कर लाभ उठाया जा सकता ह।

भारतीय वास्तुशास्त्रों के अनुसार कार्यालय की बिल्डिंग के लिए उसका प्लॉट चौकोर या आयताकार होना सबसे लाभकारी होता है। अनियमित आकार के भूखंडों से बचने का सुझाव इन ग्रंथों में दिया गया है। कार्यालय के बॉस या कंपनी के मालिक के बैठने का स्थान ऐसा होना चाहिए, जहां किसी आगंतुक की दृष्टि सीधे उसपे न पड़े। इसके लिए ग्रंथों में दक्षिण-पश्चिम कोने में केबिन बनाने का सुझाव दिया गया है और उनका मुख उत्तर दिशा की और सर्वोत्तम माना गया है। कार्यालय के सीनियर स्टाफ के लिए दक्षिण और पश्चिम में बैठना काफी वास्तुसम्मत माना गया है। साथ ही यह भी सुझाव है कि जब वे दक्षिण में बैठे हों, उनका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए और पश्चिम में बैठते समय पूर्व का सामना करना चाहिए. जबकि ऑफिस के जूनियर स्टाफ के लिए पूर्व और उत्तरी भाग की जगह सर्वोत्तम मानी गई है।

रेसिपी

चटपटे राम लड्डू

सामग्री

200 ग्राम अंकुरित मूंग दाल, 60 ग्राम अंकुरित चना दाल, पानी, 2 टीस्पून भूना हुआ जीरा, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून धनिया, 1/8 टीस्पून हींग,1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून नमक, हरी चटनी स्वादअनुसार, इमली की चटनी, मूली, धनिया, चाट मसाला

विधि

मूंग दाल और चने की दाल को 3-4 घंटों के लिए पानी में भिगोकर रखें। ब्लेंडर में दोनों दालों को डालकर पीसकर पेस्ट तैयार कर लें और फिर इसे एक बाउल में निकाल लें। अब इसमें जीरा, अदरक का पेस्ट, धनिया, हींग, लाल मिर्च, बेकिंग सोडा और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। एक पैन में तेल गर्म करें। अब इसे पकौड़ों की तरह फाई कर लें। इन्हें तबतक फाई करें जब तक इसका रंग गोल्डन न हो जाएं। अब तैयार किए लड्डू पर हरी चटनी, इमली की चटनी, मूली और धनिए के साथ गार्निश करें। फिर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क कर सर्व करें।

कॉर्न चीज़ बॉल्स

साम्रगी

170 ग्राम उबले हुए आलू, 220 ग्राम स्वीट कॉर्न, 70 ग्राम मोत्ज़ारेला पनीर, 1 टेबलस्पून मैदा, 1 1/2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 1/2 टीस्पून गर्म मसाला, 3/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून अजवायन की पत्ती, 1/2 टीस्पून नमक, मैदा, पानी, ब्रेडम्ब्स

विधि

एक बाउल में उबले हुए आलू और स्वीट कॉर्न डालकर अच्छे से मैश करें। अब इसमें मोत्ज़ारेला पनीर, मैदा,कॉर्न फ्लोर, लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च, अजवायन की पत्ती और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा-सा मिक्सर लेकर छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर साइड पर रख दें। एक अन्य बाउल में मैदा और पानी डालकर घोल तैयार कर लें। तैयार की बाउल में को मैदे के मिक्सर में डिप करके ब्रेडक्रम्ब्स में रोल करें। एक कड़ाही में तेल गर्म करके बाउल्स को फाई कर लें। कॉर्न चीज़ बॉल्स तैयार है। इन्हें गर्मा-गर्म सर्व करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

रामभक्तों पर गोली चलवाने वाले आस्था की दुहाई दे रहे

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को रामपुर पहुंचे. यहां उन्होंने सपा पर तीखा हमला बोला. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में पहचान का संकट था, बेटियां और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे. नौजवानों के पास रोजगार नहीं था. जब भी कोई सरकारी विज्ञापन या भर्ती निकलती थी, तो चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी. इस धांधली के कारण न्यायालय को भर्तियों पर रोक लगानी पड़ती थी. विकास कार्यों जैसे सड़क और पुल के लिए सरकार के पास कोई पैसा नहीं होता था. तब केवल दो लोगों का विकास होता था- एक सैफई परिवार और दूसरा रामपुर का एक परिवार.अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा विवाद के बीच सीएम योगी ने कहा कि आज भगवान रामभक्ति की दुहाई कौन दे रहा है! 2017 के पहले जो जय श्रीराम बोलने पर जो लाठी मारते थे. 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में रामभक्त कहता था कि 卐रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।

टीएमसी को झटका, 60 दिन तक सभाओं पर रोक

नईदिल्ली। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है. कोलकाता पुलिस ने मध्य कोलकाता के कुछ हिस्सों में अगले 60 दिनों के लिए रैलियों और सभाओं पर रोक लगा दी है. इस आदेश के बाद अब इन इलाकों में पांच या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी. इसके साथ ही किसी भी तरह की रैली, बैठक, जुलूस, धरना प्रदर्शन और लाठी या हथियार ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. 21 जुलाई को ञस्ष्ट की शहीद दिवस रैली होने वाली है, अब पुलिस का ये आदेश पार्टी की रैली पर असर डाल सकता है. ये फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 की धारा 163 के तहत लिया गया है. पुलिस कमिश्नर अजय नंद के मुताबिक, ये पाबंदी 2 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक लागू रहेगी. इस आदेश के तहत बोबजार थाना, हरे स्ट्रीट थाना और हेडक्वार्टर ट्रैफिक गार्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों पर पाबंदी लगी रहेगी.

दिल्ली में शुरू हो गया विशेष गहन पुनरीक्षण

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 30 जून से एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का काम शुरू हो गया है. दिल्ली में एसआईआर के लिए 13 हजार से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की ड्यूटी लगाई गई है. एसआईआर का यह पहला चरण 29 जुलाई तक चलेगा. इस दौरान केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे और मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे. हर वोटर को फॉर्म की दो प्रतियां दी जाएंगी. एक प्रति मतदाता के पास रसीद के तौर पर रह जाएगी और दूसरी बीएलओ के पास जमा करानी होगी. इस फॉर्म पर 2002 में हुए एसआईआर के मुताबिक विवरण भरने होंगे. अगर कोई मतदाता ऐसा है, जो 2002 की एसआईआर के समय किसी और राज्य का वोटर था तो वह पुराने राज्य की एसआईआर की डिटेल्स भर सकता है।

हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा के खिलाफ आपत्तिजनक दस्तावेज हटाने को कहा

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें आंशिक राहत दे दी है। अदालत ने सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों पर प्रसारित पांच आपत्तिजनक दस्तावेज हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने या उनके व्यक्तित्व अधिकारों (पर्सनैलिटी राइट्स) की सुरक्षा के लिए कोई व्यापक अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। इस आदेश के आधार पर कहा जा रहा है कि राजनीतिक आलोचनाओं वाली सामग्री नहीं हटाई जा सकेगी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने कहा कि जिन पांच दस्तावेजों पर याचिकाकर्ता ने विशेष आपत्ति जताई थी, उन्हें हटाया जाए।

सपा के चीफ व्हिप कमाल अख्तर ने दिया इस्तीफा

लखनऊ। समाजवादी पार्टी में अंदरूनी खींचतान के बीच यूपी विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक और मुरादाबाद जिले की कांठ सीट से विधायक कमाल अख्तर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है. कमाल अख्तर का अचानक इस्तीफा देना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, हाल ही में मुरादाबाद में आयोजित पीडीए पंचायत के बाद पार्टी के भीतर मतभेद खुलकर सामने आए थे. मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई थीं. इसके बाद उन्होंने पार्टी संगठन के कामकाज को लेकर नाराजगी जताई थी. सूत्रों के मुताबिक, रुचि वीरा ने अखिलेश यादव से शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि जिला संगठन एकतरफा तरीके से काम कर रहा है और उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है. हालांकि, रुचि वीरा ने सीधे तौर पर कमाल अख्तर का नाम नहीं लिया था, लेकिन पार्टी के भीतर यह माना जा रहा था कि उनका इशारा उन्हीं की तरफ था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14,115 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी

दिल्ली को मिलेगी छह लेन की टनल, यूपी में बनेगा चार लेन का हाईवे

नईदिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में छह लेन की द्वारका टनल के निर्माण को मंजूरी दी है। यह आठ किलोमीटर लंबी होगी और इस पर करीब 6,970 करोड़ रुपये की लागत आएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने यूपी के कानपुर से कबराई के बीच एक चार लेन के राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने वाले बड़े कैबिनेट फैसलों का एलान किया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को दिल्ली और उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को विश्वस्तरीय बनाने के लिए कुल 14,115 करोड़ रुपये की दो प्रमुख सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन फैसलों में दिल्ली के अंदर एक नई छह लेन की द्वारका टनल और उत्तर प्रदेश में कानपुर से कबरई तक चार लेन हाईवे का निर्माण शामिल है। यह कदम न सिर्फ ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएगा, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे में एक बड़ा रणनीतिक निवेश भी है।

देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एनएच-148एई पर छह लेन के टनल के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। यह अहम प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेस-वे (एनएच-248 बीबी) पर मौजूद शिवमूर्ति इंटरचेंज को वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग से सीधा जोड़ेगा। इस नई कनेक्टिविटी के स्थापित होने से पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली के बीच आवाजाही काफी तेज हो जाएगी, जिससे रोजमर्रा के यात्रियों के समय की भारी बचत होगी।

इस पूरी द्वारका टनल परियोजना की कुल लंबाई 8.1 किलोमीटर होगी। इंजीनियरिंग और पर्यावरण के लिहाज से इसकी सबसे बड़ी

खूबी यह है कि कुल लंबाई में से 3.1 किलोमीटर का हिस्सा सदर्न रिज फॉरेस्ट के नीचे से होकर गुजरेगा। यह एक ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है जिसे हाइब्रिड एन्यूटी मोड (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 6,970 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है और इसके निर्माण की समय सीमा 5 वर्ष तय की गई है।

दिल्ली के साथ-साथ यूपी के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने कानपुर से कबरई तक एक नया चार लेन के एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाली इस बड़ी हाईवे परियोजना पर कुल 7,145 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानपुर से कबराई तक 242 किलोमीटर लंबे चार लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर कुल 7,145 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना ढाई साल में पूरी होने की उम्मीद है।

यह नया हाईवे भोपाल-कानपुर आर्थिक गलियारे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इसके निर्माण से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह हाईवे कानपुर, हमीरपुर और महोबा जैसे जिलों से होकर गुजरेगा। महोबा एक आकांक्षी जिला है, जिसे इस परियोजना से विशेष लाभ मिलेगा। परियोजना का उद्देश्य इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और विकास को गति देना है। इसे बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) टोल मॉडल पर विकसित किया जाएगा। यह मॉडल निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इससे सरकार पर वित्तीय बोझ कम होगा। हाईवे में चार या छह लेन और पक्की शोल्डर कैरिजवे शामिल होगी। यह सुरक्षित और सुगम यात्रा प्रदान करेगा।

यह हाईवे चार लेन का होगा, जिसमें जरूरत पड़ने पर इसे छह लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इसमें पक्की शोल्डर कैरिजवे भी शामिल होगी, जिससे वाहन चालकों को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। यह एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, जिसका अर्थ है कि प्रवेश और निकास केवल निर्धारित स्थानों से ही होगा। इससे यातायात का प्रवाह सुचारु रहेगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। यह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिससे यात्रा का अनुभव बेहतर बनेगा। यह हाईवे कानपुर, हमीरपुर और महोबा जैसे जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। विशेष रूप से, महोबा जैसे आकांक्षी जिले के लिए यह विकास का नया द्वार खोलेगा। परियोजना से व्यापार, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह क्षेत्र की समग्र आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा। कुल 14,115 करोड़ रुपये (दिल्ली के लिए 6,970 करोड़ रुपये और यूपी के लिए 7,145 करोड़ रुपये) के आउटले वाली ये दोनों परियोजनाएं सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का स्पष्ट संकेत हैं।

भाजपा कार्यकर्ता ने किया टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का विरोध

नदिया। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा को बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। यह घटना पलाशी में हुई, जब वह 21 जुलाई शहीद दिवस कार्यक्रम की तैयारी से जुड़ी एक बैठक में शामिल होने आई थीं। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेस्तरां के बाहर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया और उन पर अंडे फेंके।

मोइत्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके कृष्णानगर स्थित कार्यालय पर अंडे और सब्जियां फेंककर हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें भीड़ को उन पर अंडे फेंकते हुए देखा गया। उन्होंने लिखा, इस समय मुझ पर भाजपा के गुंडों द्वारा हमला किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल पुलिस देख रही है।

उन्होंने कहा, देखिए क्या हो रहा है। पुलिस के सामने यह भाजपा की भीड़ है। मैं पिछले एक घंटे से यहां खड़ी हूं। मैंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अन्य सभी को फोन किया है। लेकिन पुलिस बैठकर देख रही है। सीआरपीएफ भी देख रही है।

महुआ मोइत्रा ने आगे कहा, यह मेरा इलाका है। मैं यहां की सांसद हूं। मैं अपने कार्यालय में हूं। मैं यहां से नहीं जाऊंगी। कृपया इनके चेहरे देखिए। कल पश्चिम बंगाल सरकार इसे नकार देगी। कोई पुलिस संज्ञान नहीं लेगी। कोई अदालत संज्ञान नहीं लेगी। सीआरपीएफ देख रही है।

सचिन अहीर बने महाराष्ट्र विधान परिषद के उपाध्यक्ष

विपक्ष के नामांकन वापसी के बाद निर्विरोध चुने गए

मुंबई। शिवसेना विधान परिषद सदस्य सचिन अहीर बुधवार को महाराष्ट्र विधान परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने विपक्ष से अपना नामांकन वापस लेने का अनुरोध किया, जिसके बाद विपक्षी उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद सदन में एक प्रस्ताव पारित किया गया और सचिन अहीर को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र विधान परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया।

महाराष्ट्र विधान परिषद में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव बुधवार दोपहर 1 बजे हुआ। महायुति शिवसेना (शिंदे गुट) के एमएलसी सचिन अहीर और महाविकास अघाड़ी (एमवीए) के एमएलसी जेएम अभ्यंकर (ठाकरे गुट) के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। एकनाथ शिंदे ने सचिन अहीर के पार्टी में शामिल होने और उम्मीदवारी को पूरी तरह गुप्त रखा। हालांकि, अंतिम समय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, चंद्रकांत पाटिल और नीलम गोरहे की उपस्थिति में सचिन अहीर का नामांकन दाखिल किया गया।

इस घटनाक्रम का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसात ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के भीतर आंतरिक कलह की अफवाहों को खारिज कर दिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम सभी ने सचिन अहीर के आगमन का स्वागत किया है, जो हमारे हित में हुआ है। इससे कोई नाराज नहीं है। ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। चाहे बात मंत्रिमंडल के विस्तार की हो या उपसभापति पद की, हर किसी की ऐसी आकांक्षाएं होती हैं, हालांकि सबकी आकांक्षाएं पूरी नहीं होतीं, इसलिए कभी-कभी असंतोष देखने को मिलता है। एकनाथ शिंदे इन आकांक्षाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे।

उन्होंने आगे कहा, हमें लगता है कि हमारे पास 13 से 14 सांसद हैं, जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हमें उसमें जगह मिलनी चाहिए। एकनाथ शिंदे इस बारे में केंद्र के वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें मंत्री पद मिल जाएगा। मंगलवार को सचिन अहीर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। सचिन अहीर का यह कदम छह शिवसेना (यूबीटी) लोकसभा सांसदों के शिंदे खेमे में शामिल होने के एक सप्ताह बाद आया है, जिसे उपमुख्यमंत्री ने ऑपरेशन टाइगर नाम दिया था।

इसी बीच, सचिन अहीर के शिंदे गुट में शामिल होने पर महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा, यह किसी तरह का ऑपरेशन नहीं है; बल्कि यह एकनाथ शिंदे पर रखे गए भरोसे का प्रतीक है। सचिन अहीर तीन बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। हमें खुशी है कि एक सक्षम कार्यकर्ता नेता, जो किसानों की आवाज भी हैं, आज हमारे साथ जुड़ गए हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

वेस्टइंडीज दौरे के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 12 जुलाई से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में सबसे बड़ा आकर्षण तेज गेंदबाज मैथ्यू फिशर हैं, जिन्हें पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है। फिशर अब तक एक टेस्ट और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक वनडे कैप नहीं मिली है। ऐसे में इस दौरे पर उनके वनडे डेब्यू की पूरी संभावना है।

आईपीएल 2026 में व्यस्त रहने के कारण बांग्लादेश दौरे से बाहर रहे नियमित कप्तान मिशेल सेंटनर एक बार फिर टीम की कमान संभालेंगे। उनके अलावा डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल और जैकब डफी की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। जैकब डफी हाल ही में पितृत्व अवकाश के कारण इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाए थे। बांग्लादेश दौरे पर खेलने वाले मुहम्मद अब्बास, आदि अशोक, जोश क्लार्कसन, डेन क्लीवर, विल ओ रूर्क और ब्लेयर टिकनर को इस बार टीम से बाहर कर दिया गया है। वहीं तेज गेंदबाज मैट हेनरी, काइल जैमीसन और विल ओ रूर्क को इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है। ब्लेयर टिकनर टखने की सर्जरी के कारण उपलब्ध नहीं रहेंगे। वनडे सीरीज के पहले तीन मुकाबले 12, 14 और 17 जुलाई को प्रोविडेंस, गुयाना में खेले जाएंगे। इसके बाद आखिरी दो मैच 20 और 22 जुलाई को केंसिंग्टन ओवल, बारबाडोस में आयोजित होंगे।

न्यूजीलैंड की वनडे टीम- मिशेल सेंटनर (कप्तान), टॉम लैथम, मिशेल हे (विकेटकीपर), मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, निक केली, विल यंग, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, क्रिस्टियन क्लार्क, माइकल ब्रेसवेल, नाथन स्मिथ, मैथ्यू फिशर, जैकब डफी, बेन सियर्स, जेडन लेनोक्स।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 444 अंक चढ़ा निफ्टी 24,000 के पार बंद

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजार ने सप्ताह के पहले कारोबारी दिन मजबूती के साथ कारोबार समाप्त किया। एफएमसीजी, रियल्टी, बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में जोरदार खरीदारी के दम पर प्रमुख सूचकांकों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी50 140.10 अंक यानी 0.59 फीसदी की बढ़त के साथ 24,005.85 पर बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स 443.97 अंक यानी 0.58 फीसदी चढ़कर 76,922.64 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी50 में Eternal, अदाणी इंटरप्राइसेस और नेस्ले इंडिया सबसे अधिक बढ़त दर्ज करने वाले शेयर रहे। सेंसेक्स के 30 शेयरों में Eternal, एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अदाणी पोर्ट्स के शेयर सबसे अधिक बढ़त के साथ कारोबार करते नजर आए। इन शेयरों में खरीदारी के दम पर बाजार को मजबूती मिली।

पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए हुआ सस्ता

नईदिल्ली। नायरा एनर्जी ने आम जनता को राहत देते हुए 1 जुलाई 2026, से ईंधन के दामों में बड़ी कटौती की है। नायरा एनर्जी ने अपने पूरे देश के रिटेल नेटवर्क पर पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की। वेस्ट एशिया में तनाव कम होने से ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतें गिरीं, जिसके बाद दो साल से ज्यादा समय में पंप की कीमतें घटाने वाली यह पहली फ्यूल रिटेलर कंपनी बन गई है। नई कीमतें देश भर में नायरा के 7,000 से ज्यादा फ्यूल स्टेशनों पर लागू हो गई हैं, हालांकि अंतिम रिटेल कीमत राज्यों में अलग-अलग हो सकती है, जो वेट जैसे स्थानीय टैक्स पर निर्भर करेगा। यह कदम मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने और एक अहम समुद्री रास्ते के फिर से खुलने के बाद इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद उठाया गया है।

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 183.50 रुपए घटे

नईदिल्ली। एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए राहत की खबर है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 जुलाई से 19-किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम कर दी है, जिससे दिल्ली में इसकी रिटेल कीमत 2,930 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। कीमतें 183.50 रुपये कम की गई हैं, जो 1 जुलाई से लागू हैं। कमर्शियल एलपीजी की दरों में कटौती के अलावा, तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 5-किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडर की कीमत भी 13 रुपये कम की है। इस बदलाव के बाद दिल्ली में 5-किलो वाले एफटीएल सिलेंडर की रिटेल कीमत अब 808.50 रुपये हो गई है। कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में यह हालिया कटौती हाल के महीनों में कीमतों में कई बदलावों के बाद हुई है। इससे पहले, जून में घरेलू एलपीजी की कीमतें 29 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाई गई थीं।

महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल बिक्री जून में 37% बढ़ा

मुंबई। महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) लिमिटेड की निर्यात सहित कुल बिक्री जून में 37 प्रतिशत बढ़कर 1,06,207 इकाई हो गई। पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 77,742 इकाई थी। कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि जून 2025 में 47,306 इकाई की तुलना में जून 2026 में उसकी घरेलू एसयूवी बिक्री 28 प्रतिशत बढ़कर 60,393 इकाई हो गई। बयान के अनुसार, जून में कंपनी की घरेलू वाणिज्यिक वाहन बिक्री 35 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ 26,076 इकाई रही। इस बीच, एक अलग बयान में महिंद्रा समूह के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस ने बताया कि जून 2026 में उसकी कुल ट्रैक्टर बिक्री 12% बढ़कर 59,935 इकाई रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 53,392 इकाई थी। इसमें घरेलू ट्रैक्टर बिक्री 12% बढ़कर 58,177 इकाई रही।

विकसित भारत के लिए नीतियों और अभियानों से ज्यादा गतिशील संस्थाओं की जरूरत

जयंत सिन्हा

भारत एक दुर्लभ मोड़ पर खड़ा है। अगले 10 से 15 वर्षों तक उसके पास सतत समृद्धि हासिल करने और एक उच्च आय वाला देश, एक विकसित भारत, बनने के अपार अवसर हैं। तीन अवसर खुले हैं, और एक-दो दशक में तीनों ही समाप्त हो जाएंगे। ये हैं- जनसंख्या का अवसर : 2030 के दशक के आरंभ से मध्य तक हमारी कार्यशील आयु वर्ग की हिस्सेदारी और निर्भरता अनुपात सबसे अनुकूल रहेगा और उसके बाद इसमें लगातार गिरावट शुरू हो जाएगी। ऊर्जा का अवसर: इस दशक में स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं और निवेश की नींव रखी जा रही है।

प्रौद्योगिकी का अवसर: आर्टिफिशल इंटेलिजेंस वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में आ गई है, और एआई युग के नियम अब तय किए जा रहे हैं। हमें इन तीनों अवसरों का लाभ उठाना चाहिए जब तक ये खुले हैं।

हिसाब बिल्कुल साफ है। भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,700 डॉलर है, उच्च आय की सीमा लगभग 14,000 डॉलर है। विश्व बैंक के अनुसार, 1990 के बाद से केवल 34 अर्थव्यवस्थाओं ने ही यह छलांग लगाई है, जिनमें से अधिकतर छोटी या संसाधन संपन्न हैं। 140 करोड़ की आबादी वाला चीन एक ही पीढ़ी में इस सीमा को पार करने वाला है, इसलिए हमारे जैसे देश भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमें एक पीढ़ी तक प्रति व्यक्ति आय में हर साल लगभग 7 फीसदी की वृद्धि की आवश्यकता है।

इसके अलावा, जैसे-जैसे समृद्ध देश आप्रवासन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को विदेश में कम अवसर मिलेंगे, इसलिए हमें देश में ही अवसर पैदा करने होंगे।

चीन केंद्रीय नियोजन, एकदलीय शासन

की निरंतरता और पूंजी पर पूर्ण नियंत्रण के माध्यम से इस मुकाम तक पहुंचा है, एक ऐसा रास्ता जिसका अनुसरण भारत न तो कर सकता है और न ही करना चाहिए। भारत एक संघीय लोकतंत्र है, जिसमें स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र चुनाव, स्वतंत्र प्रेस और एक ऐसा संघ है जिसे राज्यों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमें एक अलग मार्ग अपनाना होगा।

हम इस रास्ते को किसी व्यापक नीतिगत पैकेज या राष्ट्र निर्माण के नए अभियानों के माध्यम से नहीं खोज पाएंगे। भारत में नीतियों या अभियानों की कमी नहीं है। बल्कि, यहां गतिशील संस्थानों की कमी है जो इन्हें टिकाऊ, अनुकूलनीय और जवाबदेह बना सकें। नेता, नीतियां और अभियान सभी आवश्यक हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। असली काम संस्थागत स्तर पर नियमों में है। हमारी राष्ट्रीय बहस का एक बड़ा हिस्सा नीतिगत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए संस्थागत ढांचे को नजरअंदाज कर देता है। अगले 15 वर्षों का लक्ष्य ऐसी संस्थागत संरचना का निर्माण करना है जिसके माध्यम से प्रमुख पहलें राजनीतिक चक्रों से परे जा सकें, प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें, पूंजी जुटा सकें और व्यापक स्तर पर परिणाम दे सकें।

भारत गतिशील संस्थाओं का निर्माण करना जानता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम खर्च में मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफल हुआ, और यह सब उसकी तकनीकी स्वायत्तता की रक्षा करने वाली संस्कृति के कारण संभव हुआ। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद में केंद्र को एक तिहाई और राज्यों को दो तिहाई मत दिए गए हैं और लगभग सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।

एक गतिशील संस्था को तीन कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए। यह सक्षम, विधिसम्मत और जवाबदेह होनी चाहिए। एक सक्षम संस्था में निरंतर पेशेवर नेतृत्व, स्थिर वित्तपोषण, तकनीकी स्वायत्तता और अनुकूलन क्षमता होती है, जिससे वह दीर्घकालिक परिणाम दे सकती है। एक विधिसम्मत संस्था टिकाऊ कानून, स्पष्ट जनादेश और समीक्षा योग्य निर्णयों पर आधारित होती है, जिससे नागरिक और निवेशक नियमों पर भरोसा कर सकें।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक

एआई के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनेगा छत्तीसगढ़: सीएम साय

■ मोबाइल नेटवर्क विस्तार, भारतनेट फेज-3, सेवा सेतु और डिजिटल नवाचार परियोजनाओं की समीक्षा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के विकास एवं विस्तार, मोबाइल नेटवर्क सुदृढ़ीकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी, सेवा सेतु, ई-प्रगति पारस (प्रोजेक्ट असेसमेंट रिव्यू एवं एनालिसिस सिस्टम), सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेटा लैब्स तथा विभिन्न डिजिटल नवाचार परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। इसके साथ ही युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने तथा तकनीक आधारित सुशासन को नई गति देने के विभिन्न आयामों पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और राज्य इस क्षेत्र में देश का अग्रणी प्रदेश बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि एआई केवल भविष्य की तकनीक नहीं, बल्कि सुशासन, पारदर्शिता, दक्षता और जनसेवा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रभावी माध्यम है। एआई के प्रभावी उपयोग से शासन-प्रशासन को अधिक सक्षम, पारदर्शी, त्वरित एवं नागरिक-केंद्रित बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल नई तकनीक को अपनाना नहीं है, बल्कि प्रदेश के लोगों को एआई के लिए तैयार करना, व्यवसायों की उत्पादकता बढ़ाना, नागरिकों की आय में वृद्धि करना तथा बेहतर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास और दैनिक प्रशासनिक कार्यों में एआई के

व्यापक उपयोग से आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य में मजबूत एआई इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा तथा सुरक्षित, विश्वसनीय और जिम्मेदार एआई के उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में प्रस्तुत विजन दस्तावेज में बताया गया कि राज्य का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को एआई के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है, जहां प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा में एआई सीख सके, सरकार तकनीक आधारित भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करे और उद्योगों तथा व्यवसायों को नई गति मिले। इस मिशन के अंतर्गत पांच प्रमुख स्तंभों - एआई कौशल विकास, नवाचार एवं स्टार्टअप, जागरूकता एवं आउटरीच, सुरक्षित एवं जिम्मेदार एआई तथा शासन में एआई के उपयोग - पर कार्य किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में विद्यार्थियों तथा सरकारी कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्कूलों में एआई जागरूकता कार्यक्रम, एआई एवं रोबोटिक्स क्लब तथा हैकाथॉन आयोजित किए जाएंगे। महाविद्यालयों में एआई सर्टिफिकेशन कार्यक्रम, छात्र परियोजनाओं के लिए अनुदान, आईटीआई में एआई लैब तथा विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। राज्य में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एआई डेटा लैब्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एआई आधारित स्टार्टअप, डेटा सेट तथा अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा, सीड फंडिंग तथा उद्योगों एवं शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से अत्याधुनिक एआई आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने की भी कार्ययोजना प्रस्तुत की गई।बैठक में सुरक्षित एवं जिम्मेदार एआई उपयोग को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य स्तर पर एआई नीति तैयार की जाएगी, जिसमें डेटा सुरक्षा, नागरिकों की निजता का संरक्षण, नियमित तकनीकी ऑडिट तथा केंद्र सरकार के डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के अनुरूप व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। शासन में एआई के प्रभावी उपयोग के लिए विभिन्न विभागों में एआई आधारित निर्णय सहायता प्रणाली विकसित की जाएगी, प्रत्येक विभाग का अलग रोडमैप तैयार होगा, एआई नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी एआई पायलट परियोजनाएं प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भाषिणी प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जाएगा।

नकटी की तोड़-फोड़ अमानवीयः बैज

रायपुर। राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नकटी गांव में 85 आवास एवं प्रधानमंत्री आवास के मकानों की तोड़-फोड़ साय सरकार और भाजपा के गरीब विरोधी चेहरे को उजागर करता है। नकटी की तोड़-फोड़ अमानवीय अनैतिक तो है ही यह तोड़-फोड़ गैरकानूनी भी है। अमूमन मानवीय आधार पर बारिश के समय विस्थापन की कार्यवाही नहीं की जाती है, यह छत्तीसगढ़ में 10 जून से 15 जून मानसून आने का समय माना जाता है। इस समय के बाद राज्य के जमीनों का सीमांकन भी नहीं किया जाता है। नकटी गांव में तोड़-फोड़ की कार्यवाही 29 जून को की गयी है, जो पूरी तरह से गलत और गैरकानूनी प्रक्रिया है। इस कार्यवाही में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। सरकार कानूनी कार्यवाही नहीं करेगी तो हम इस मामले को लेकर कोर्ट भी जायेंगे। किसी भी विस्थापन की कार्यवाही के पहले व्यवस्थापन होना था, सरकार ने बिना व्यवस्थापन कार्य को पूरा किये वहां पर रह रहे लोगो को समान हटाने का अवसर दिये बिना तोड़-फोड़ किया, उनके घरो में बुलडोजर चलवाया। जहां पर व्यवस्थापन किया जा रहा है, वह भी वर्तमान निवास से बहुत दूर है।

1 कमरे के घर में 20 से 25 सदस्यीय परिवार को व्यवस्थापन दिया गया है। उनका गुजारा कैसे होगा? वहां पर बिजली, पानी जैसी मूलभूत जरूरते भी नहीं है। सरकार ने प्रभावितों को जो अस्थायी आवंटन पत्र दिया है उसके अनुसार 5.50 लाख, 8.50 लाख दो श्रेणी के मकान दिया है। इसका राशि का भुगतान कौन करेगा? इसको पूरा निःशुल्क क्यों नहीं किया गया?

कांग्रेस के आदिवासी विधायक जनक ध्रुव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नकटी में विधायक आवास लेने से मना कर दिया है। हमारी अनुसूचित जाति की महिला विधायक चातुरी नंद ने भी वहां पर आवास लेने से मना किया है, उनका कहना है वे भी गरीबों के आशियाना उजाड़ कर बनाये गये मकान पर अपना घर नहीं बसायेंगे। हम, कांग्रेस और भाजपा के विधायकों से भी आग्रह करते है कि गरीबों की आह लेकर बनाई जा रही इस कॉलोनी में आवास लेने से मना करें।

शिक्षा से ही बनेगा उज्ज्वल भविष्यः कश्यप

भानपुरी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया शाला प्रवेश उत्सव

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बस्तर जिले के भानपुरी में शाला प्रवेश उत्सव उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में दोनों अतिथियों ने नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। बच्चों को स्कूल बैग और अन्य शैक्षणिक सामग्री भी वितरित की गई। वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि शिक्षा एक मजबूत और विकसित समाज की सबसे बड़ी आधारशिला है। राज्य सरकार का उद्देश्य हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना और विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने सभी बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजें, ताकि वे शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर सकें।

सांसद महेश कश्यप ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत और लगन से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आधुनिक शिक्षा और तकनीक का लाभ उठाकर वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।

शाला प्रवेश उत्सव के अवसर पर ग्राम बनियागांव में 1 करोड़ 12 लाख 80 हजार रुपये की लागत से निर्मित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया गया। नए भवन से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर और सुविधायुक्त वातावरण में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम में विद्यालयों को डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट टीवी प्रदान किए गए। साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया।

भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने केवल अपने पद से ही नहीं, बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र दे दिया है। जानकारी के अनुसार, रवि भगत ने अपना इस्तीफा संबंधित मंडल अध्यक्ष को भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अपना इस्तीफा सार्वजनिक रूप से साझा किया है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

रवि भगत भाजपा युवा मोर्चा में लंबे समय तक सक्रिय रहे हैं और संगठन में उनकी मजबूत पहचान रही है। वे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, जिससे संगठनात्मक स्तर पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती रही है। हाल के समय में रवि भगत पार्टी की कार्यशैली और कुछ निर्णयों को लेकर असंतोष जाहिर करते नजर आए थे। विभिन्न सार्वजनिक बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कई बार संगठनात्मक मुद्दों पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी। उनके इस इस्तीफे को पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और आंतरिक मतभेदों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, उन्होंने अपने इस्तीफे में स्पष्ट कारणों का विस्तृत उल्लेख सार्वजनिक रूप से नहीं किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम से भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में युवाओं से जुड़े नेतृत्व को लेकर नई चर्चा शुरू हो सकती है।

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बस्तर संभाग की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की

रायपुर। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने आज बुधवार को बस्तर कलेक्टोरेट के प्रेरणा सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं एवं शैक्षणिक गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि बस्तर के समग्र विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अंदरूनी क्षेत्रों के स्कूलों को पुनर्जीवित करने, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण विकसित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने प्राथमिक स्तर पर गणित, हिंदी और अंग्रेजी की मजबूत आधारशिला तैयार करने के लिए कैलेंडरवार, शालावार एवं विषयवार समय-सारणी के अनुसार पढ़ाई कराने तथा नियमित रिवीजन टेस्ट आयोजित करने के निर्देश दिए।

बैठक में शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, संचालक ऋतुराज रघुवंशी, कलेक्टरआकाश छिकारा, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, संभागीय संयुक्त संचालक एच.आर. सोम सहित सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, डीएमसी, बीईओ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान आधार बेस ऐप के माध्यम से कार्यालयीन अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति तथा वीएसके ऐप में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की जानकारी ली गई। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा नेटवर्क विहीन स्कूलों की सूची कलेक्टर के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। अन्य विभागों में पदस्थ शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को मूल पदस्थापना पर वापस भेजने संबंधी निर्देशों के पालन की भी समीक्षा की। श्री यादव ने बसाहटवार प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति, नए विद्यालयों की आवश्यकता, बंद स्कूलों को पुनः प्रारंभ करने की कार्ययोजना, बोर्ड एवं वार्षिक परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हुए पोटा केबिनों में अंतरजिला विद्यार्थियों को प्रवेश देने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा मंच

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को नई पहचान देने और लोक एवं शास्त्रीय कलाओं को व्यापक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2026-27 के वार्षिक सांस्कृतिक आयोजनों के लिए कलाकारों एवं सांस्कृतिक दलों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग द्वारा आयोजित इन प्रतिष्ठित आयोजनों के माध्यम से प्रदेश के प्रतिभाशाली कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, वहीं विलुप्त होती लोक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन को भी नई गति मिलेगी। संस्कृति विभाग प्रतिवर्ष प्रदेशभर में विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों का आयोजन करता है, जिनमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोकसंगीत, लोकनृत्य, नाट्य प्रस्तुतियां तथा पारंपरिक वाद्ययंत्रों की प्रस्तुतियां शामिल रहती हैं। इसी क्रम में वर्ष 2026-27 के लिए पावस प्रसंग (शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य), रंगतरंग वाद्ययंत्र संगम, रंगपरब नाट्य श्रृंखला तथा लोकरंग पर्व के लिए कलाकारों का चयन किया जाएगा। विशेष रूप से लोकरंग पर्व के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोककलाओं एवं लोकविधाओं से जुड़े कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

रायपुर नगर पालिक निगम के 11 एल्डरमैन 2 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगे

रायपुर। छत्तीसगढ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा रायपुर नगर पालिक निगम के लिये घोषित किए 11 एल्डरमैन को 2 जुलाई को कलेक्टर द्वारा शपथ दिलाई जायेगी।

शासन द्वारा नगर निगम रायपुर के घोषित एल्डरमैन रामकिंकर सिंह, विनय ओझा, मनीष करड़भुजे, मित्रसेन धीमान, राजू राघवानी, गोपाल सोना, बी. श्रीनिवास राव, गोपी साहू, विक्रम सिंह ठाकुर, ऋषि साहू ने बुधवार को निगम महापौर मीनल चौबे से निगम मुख्यालय कक्ष में मुलाकात की। महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने हार्दिक शुभकामनायें दीं ।

11 एल्डरमैन में रामकिंकर सिंह, विनय ओझा, मनीष करडभुजे, मित्रसेन धीमान, राजू राधवानी, गोपाल सोना, बी. निवास राव, अनिल सोनकर, गोपी साहू, विक्रम सिंह ठाकुर, ऋषि साहू शामिल हैं। ये सभी को 2 जुलाई गुरुवार को रायपुर कलेक्ट्रोरेट सभाकक्ष में शपथ ग्रहण करेंगे।

अंजय शुक्ला के जन्मदिन समारोह में जुटे शहर के विशिष्टजन

रायपुर। जैसा बोओगे वैसा पाओगे की कहावत आज भी कई मौकों पर चरितार्थ हो रहा है,ऐसा ही अवसर था मंगलवार 30 जून को जब छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष अंजय शुक्ला के जन्मदिवस का आयोजन श्री माँ महाकाली मंदिर ट्रस्ट, आकाशवाणी चौक, परिसर में किया गया था जहां मंत्री से लेकर एक आदमी तक की उपस्थिति ने साबित कर दिया कि हर किसी के सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले अंजय शुक्ला के जन्मदिवस पर वे क्यों न शामिल होकर खुशियों के पल का साक्षी बने। सुप्रसिद्ध कथावाचकर पं. विजयशंकर मेहता द्वारा हमारे हनुमान विषय पर एक विशेष आध्यात्मिक व्याख्यान दिया गया। व्याख्यान में हनुमान जी के जीवन चरित्र और हनुमान चालीसा की आध्यात्मिक ऊर्जा से जीवन प्रबंधन के साथ पारिवारिक जुड़ाव एवं संस्कार को अपनाने की राह दिखाई।

लक्ष्मीनारायण कन्या उमावि में मनाया शाला प्रवेश उत्सव

रायपुर। लक्ष्मीनारायण कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम गुरुकुल प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा मुख्य अतिथि के रुप में शामिल हुईं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि तरल मोदी अध्यक्ष भातखण्डे ललितकला शिक्षा समिति एवं अध्यक्षता श्री अजय तिवारी उपाध्यक्ष ने किया। समिति की सचिव श्रीमती शोभा खण्डेलवाल, गुरुकुल महिला महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर श्रीमती संध्या गुप्ता के साथ कमलादेवी संगीत महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमती आरती सिंह विशेष रूप से उपस्थित हुईं। प्रवेश उत्सव में सर्वप्रथम मुख्य अथिति का स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। प्राचार्या श्रीमती मनीषा गहोई ने स्वागत भाषण के साथ प्रतिवेदन प्रतुत करते हुए अथितियों का स्वागत किया। अथितियों द्वारा नवप्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक लगाकर मुँह मीठा करवाया गया उन्हें कॉपी पुस्तक पेन वितरित किया गया। बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए मुख्य अथिति एवं अन्य अतिथियों द्वारा आशीर्वचन उद्बोधन किया गया। कार्यक्रम का संचालन सादिका सुल्ताना सिद्दिकी ने किया। इस अवसर पर शाल श्रीफल से अतिथियों का स्वागत किया गया। विद्यालय की समस्त शिक्षिका, कर्मचारियों के साथ अध्ययनरत छात्राएं उपस्थिति होकर कार्यक्रम को सफल बनाया।

मंत्रालय के तीन कर्मियों को सम्मानपूर्ण विदाई

रायपुर। राज्य शासन की सेवा में दीर्घकाल तक योगदान देने के उपरांत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए तीन अधिकारी-कर्मचारियों के सम्मान में आज मंत्रालय महानदी भवन में सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया तथा उनके स्वस्थ, सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सेवानिवृत्त होने वालों में श्रम विभाग के अवर सचिव कीर्तिवर्धन उपाध्याय, गृह विभाग के स्टाफ ऑफिसर राजेश हीरा तथा स्कूल शिक्षा विभाग के दफ्तरी चैनसिंह शामिल हैं। इस अवसर पर मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के साथ निभाई गई शासकीय सेवा सदैव प्रेरणादायी होती है। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का योगदान शासन-प्रशासन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों के स्वस्थ, सुखद एवं सम्मानपूर्ण जीवन तथा उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में बहेगी विकास की बयार

700 प्राध्यापकों की भर्ती के साथ खुलेंगे तरक्की के द्वार

रायपुर। राज्य में उच्च शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प और युवाओं को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को नया कलेवर देने और सालों से अटके प्रशासनिक मामलों को सुलझाने के लिए आज उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा की अध्यक्षता में मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए गए।

प्रदेश के उच्च शिक्षा इतिहास में युवाओं के लिए इसे सबसे बड़ा दिन कहा जा सकता है। बैठक में सबसे बड़ा और अहम फैसला लेते हुए मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने सहायक प्राध्यापक के 700 रिक्त पदों पर अविलंब भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी है

कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर कोई रुकावट या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, विभाग के अन्य खाली पदों को भरने के लिए भी शासन को तत्काल नया प्रस्ताव भेजने का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। सीजीपीएससी के माध्यम से होने वाली प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन कार्य को भी अब युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।

महाविद्यालयों में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने कड़े लहजे में निर्देश दिया कि 31 जुलाई 2026 तक स्नातक प्राचार्यों की पदोन्नति का काम हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। नए शिक्षा सत्र में छत्तीसगढ़ का कोई भी स्नातक कॉलेज बिना नियमित प्राचार्य के नहीं रहेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार के एजेंडे में शिक्षा की गुणवत्ता सबसे ऊपर है।

प्राध्यापकों और विभागीय कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए बैठक में कई संवेदनशील निर्णय लिए गए। पुराने नियम से मिलेगी तरक्की साल 2019 से पहले के बचे हुए सहायक प्राध्यापकों को 1990 के नियमों के तहत ही प्राध्यापक पद पर प्रमोट किया जाएगा, जिससे उनकी वरिष्ठता सुरक्षित रहेगी। सहायक प्राध्यापकों के वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान की सूचियां लगभग तैयार हैं, जिन्हें जल्द ही जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। लंबे समय से संघर्षरत अतिथि प्राध्यापकों की जायज मांगों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सेवा शर्तों में सुधार के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार तुरंत एक्शन लेने जा रही है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक ग्रेड-3 और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां अब %राज्य कर्मचारी चयन आयोग% के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएंगी।

राज्य सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सुदूर वनांचल और ग्रामीण क्षेत्रों के होनहारों के लिए एक अनोखी पहल की है। अब महाविद्यालयों में 90 घंटे, 90 दिन का विशेष अंग्रेजी संप्रेषण कोर्स चलाया जाएगा।

मिश्रित खेती अपनाएं किसान : नेताम

रायपुर। कृषि मंत्री ी रामविचार नेताम आज कांकेर में किसान संगोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने कांकेर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को धान के साथ दलहन-तिलहन की भी खेती करना चाहिए। उन्होंने कम पानी एवं कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाली फसलों की खेती करने को कहा। इससे पानी की बचत होगी और फायदा भी ज्यादा मिलेगा। संगोष्ठी में किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन तथा आत्मनिर्भरता दलहन-तिलहन मिशन के अंतर्गत दलहन बीज वितरित किए गए। विधायक आशाराम नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी संगोष्ठी में शामिल हुए। कृषि मंत्री नेताम ने खेत के मेड़ों में

मुनगा का पौधा लगाने, अरहर की खेती करने तथा मिश्रित खेती को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने किसानों को खेती के साथ-साथ मछलीपालन, मुर्गीपालन और पशुपालन भी करने को कहा। घर-घर में गाय के पालन से घर की जरूरत भी पूरी होगी, अतिरिक्त आमदनी होगी, पोषण मिलेगा और समृद्धि आएगी। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद के अधिकाधिक उपयोग से धरती की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। इसलिए किसान जैविक खेती को अपनाएं। उन्होंने बताया कि ऐसे किसान जिन्होंने पिछले खरीफ सीजन में धान की फसल ली थी, वे इस वर्ष खरीफ में धान के बदले अन्य फसल, मक्का या दलहन-तिलहन लगाएंगे, तो शासन द्वारा प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की आदान सहायता दी जाएगी।कृषि मंत्री नेताम ने कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर में लक्ष्मी स्वसहायता समूह द्वारा किए जा रहे मिलेट प्रोसेसिंग कार्य का भी अवलोकन किया। उन्होंने समूह की महिलाओं से चर्चा कर कोदो, कुटकी व रागी की प्रोसेसिंग और उनकी मार्केटिंग की जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि मिलेट प्रोसेसिंग से समूह के प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह लगभग छह से सात हजार रुपए की आमदनी हो रही है। नेताम ने समूह की आय आय बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के मेड़ों में चार चिरौंजी के पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.